

Ranga, Shri
Sanji Rupji, Shri
Sen, Shri P. G.
Sharma, Shri Narayan Swaroop
Shoo Narain, Shri
Shivappa, Shri N.
Singh, Shri D. N.
Singh, Shri J. B.
Solanki, Shri S. M.
Suraj Bhan, Shri
Thakur, Shri Gunanand
Vidyarthi, Shri Ram Swarup

Enacting Formula Amendment made :-

Page 1, line 1,

for 'Nineteenth' substitute 'Twenty
first'. (1)

(Shri Sher Singh)

MR. DEPUTY-SPEAKER : The ques-
tion is :

"That the Enacting Formula, as
amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

*The Enacting Formula, as amended,
was added to the Bill.*

The Title was added to the Bill.

SHRI SHER SINGH : I beg to move :

"That the Bill, as amended, be pas-
sed."

MR. DEPUTY-SPEAKER : The ques-
tion is :

"That the Bill, as amended, be pas-
sed."

The motion was adopted.

15.59 hrs.

DISCUSSION RE. MIGRATION OF
HINDU MINORITIES FROM
EAST PAKISTAN

MR. DEPUTY-SPEAKER : We shall
now take up discussion under rule 193 on
the large-scale migration of Hindu minori-
ties from East Pakistan and the steps taken
by the Government to check it.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The result*
of the division is *Ayes* : 114; *Noes* : 43

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The ques-
tion is :

"That clause 2, as amended, stand
part of the Bill."

The motion was adopted.

*Clause 2, as amended, was added
to the Bill.*

Clause 1—(Short Title, extent commence-
ment and application)

Amendment made :

Page 1, line 4,

for '1968' substitute '1970'. (2)
(Shri Sher Singh)

MR. DEPUTY-SPEAKER : The ques-
tion is :

"That clause 1, as amended, stand
part of the Bill."

The motion was adopted.

*Clause 1, as amended, was added
to the Bill.*

The following members also recorded their votes :

AYES : Shri Chandoolal Chandrakar.

NOES : Sarvshri Yajna Datt Sharma, J. Mohamed Imam, Kanwar Lal Gupta and
V. Narasimha Rao.

श्री कंबर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष जी, आप आज पूर्वी पाकिस्तान से लाखों की संख्या में हिन्दू रोजाना भारत आ रहे हैं। यह एक गम्भीर समस्या बन कर हमारे सामने खड़ी हो गई है। यह समस्या केवल बंगाल की समस्या नहीं है। सारे देश की यह समस्या है। फिर यह समस्या कोई नई नहीं है। यह कंटिन्युइंग प्रासेस है और पिछले 22 साल से लगातार चलती आ रही है।

16 hrs.

[SHRI K. N. TIWARI in the Chair]

मेरा कहना यह है कि यह एक हिस्सा है पाकिस्तान की प्लान्ड कंस्पिरेसी का। उस कांस्पिरेसी के जरिये से पाकिस्तान अपने यहां रहने वाले हर एक हिन्दू और माइनारिटी के आदमी को एक प्लान्ड बे में निकालना चाहता है और उन लोगों की प्रापर्टी को जब्त करना चाहता है। जैसा कि मैंने कहा है, आज पूर्वी बंगाल में जो कुछ हो रहा है, वह उस कांस्पिरेसी का एक हिस्सा है।

पाकिस्तान से हिन्दुओं को 1947 में निकाला गया और उस के बाद 1948, 1950, 1954, 1960 और 1965 में निकाला गया। हर एक घंटे में कभी पांच लाख लोगों को निकाल दिया गया, कभी पचास लाख लोगों को और कभी दस लोगों को निकाल दिया गया। इस के अलावा हर बार कुछ लोगों को मार दिया गया और कुछ का धर्म परिवर्तन कर दिया गया। इस तरह से एक प्लान्ड बे में यह काम चल रहा है। मेरा कहना यह है कि यह पाकिस्तान गवर्नमेंट की पालिसी का एक हिस्सा है। उस देश का चाहे कोई भी प्रधान मंत्री या राष्ट्रपति हो, इस मामले में सब की नीति एक प्रकार की रही है। पाकिस्तान की तरफ से एक और तो अपने यहाँ की माइनारिटीज को निकाला जाता है और दूसरी ओर काश्मीर और आसाम में इनफिल्ट्रेशन किया जाता है।

इतनी बड़ी संख्या में हिन्दुओं के पाकिस्तान से आने के मंत्री महोदय ने जो कारण बताए हैं, मैं उन से सहमत हूँ। वहाँ पर माइनारिटीज की कोई सिक्युरिटी नहीं है। उन की बहु-बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। वहाँ पर सरकार की मदद से जान-बूझ कर इस तरह की योजनाएँ बनाई जाती हैं कि हिन्दू पाकिस्तान को छोड़ कर चले जायें।

सवाल यह है कि पिछले बाइस साल से जो कुछ हो रहा है, उस का इलाज क्या है। मंत्री महोदय ने कहा है कि कानून के लिहाज से दोनों देशों की माइनारिटीज की जिम्मेदारी उन देशों की सरकारों की है। टेकनिकल दृष्टि से यह बात ठीक है कि हमारे देश में जो माइनारिटीज हैं, उन की जिम्मेदारी हम पर है और जो माइनारिटीज पाकिस्तान में हैं, उन की जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार पर है।

मंत्री महोदय ने कल कहा कि हम पाकिस्तान सरकार को रिमाइंडजं भेज सकते हैं, उस को याद दिला सकते हैं, उस को पर्सवेड कर सकते हैं, उस को अपील कर सकते हैं, उस से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? उस से क्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे यह बात सुन कर बहुत दुख हुआ। मैं समझता हूँ हर एक देशवासी को यह बात सुन कर दुख होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हम कुछ पग उठा रहे हैं। मैं उन से पूछना चाहता हूँ कि पिछले दो, तीन, चार साल में, या पिछले छः महीने में, उन्होंने कौन से पग उठाये हैं। उन्होंने कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से वहाँ के मंत्री को चिट्ठी लिखी है और उस ने यह विश्वास दिलाया है कि वह इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करेंगे।

इस बारे में मेरी पहली मांग यह है कि इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने जो पत्र पाकिस्तान को लिखे हैं और पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब आया है, उन को वह इस सदन

[श्री कंवर लाल गुप्त]

के टेबल पर रखे ताकि हमें मालूम हो कि वास्तव में कितनी ईमानदारी, कितनी चुस्ती और कितनी मजबूती के साथ मंत्री महोदय पाकिस्तान को लिख रहे हैं और पाकिस्तान का इस बारे में क्या रीएक्शन है। इस समय तो पाकिस्तान का रीएक्शन यही है कि लोग बहुत बड़ी संख्या में नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि आप बाइंडर सील कर दीजिये, इस में हमारी जिम्मेदारी या गलती नहीं है। उस ने हमारे किसी भी आरोप को स्वीकार नहीं किया है। इस लिए यह देश मंत्री महोदय से यह मांग करता है कि पाकिस्तान के साथ जो कारिसपांडेस हुई है, वह उस को सदन के टेबल पर रखें। मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि हम दूसरे देशों को भी इस स्थिति से अवगत कराते रहते हैं। वह यह भी बताये कि उन्होंने इस बारे में किन किन दूसरे देशों को लिखा है, ताकि हमें इस समस्या पर विचार करने में आसानी हो।

मंत्री महोदय ने कहा है कि हम और क्या कर सकते हैं। क्या यह उन की हैल्पलेसनेस का अट्टर कनफेशन नहीं है? वह अपनी मजबूरी बाहिर करते हैं कि वह कुछ नहीं कर सकते हैं। वह यह भी कहते हैं कि इस में हमारी क्या जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार की है। यह बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो हिन्दू रहते हैं, उन के प्रति हमारी विशेष जिम्मेदारी है। आप को याद होगा कि जब पाकिस्तान बना था, तो देश के सामने दो सवाल थे। एक तो यह था कि पापुलेशन का एक्सचेंज हो जाये। उस वक़्त के हमारे ब्रेथ के नेताओं ने इस को ठीक नहीं समझा। उन्होंने कहा कि हम जिन्ना की इन्वैशन थ्योरी को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने यह रास्ता बताया कि दोनों देशों में रहने वाली माइनारिटीज की जिम्मेदारी उन देशों की सरकारों पर होगी और इस बात का

ध्यान रखा जाएगा कि दोनों देशों में माइनारिटीज ठीक प्रकार से रहें। दोनों देशों की सरकारों के बीच में इसी टैसिट अंडरस्टैंडिंग पर पार्टिशन का समझौता हुआ। भारत सरकार ने पाकिस्तान से कहा कि वह अपने यहां के हिन्दुओं को ठीक तरह से रखे और हम ने अपने यहां की माइनारिटीज, मुसलमानों, की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। यह पार्टिशन का आधार था, कारालोरी थी। हम ने इस आधार को माना है। थोड़ी बहुत इधर उधर कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन भोटे तौर पर हम ने इस को माना है।

इस सरकार ने पाकिस्तान के साथ जितने भी एग््रीमेंट किये हैं नेहरू लियाकत एग््रीमेंट, नेहरू नून एग््रीमेंट, पन्त मिर्जा एग््रीमेंट और आखिर में ताशकंद एग््रीमेंट, उस में सरकार ने क्यों बार बार माइनारिटीज की रक्षा की बात को शामिल किया है? इस का साफ मतलब यह है कि सरकार भी यह समझती है कि पाकिस्तान के हिन्दुओं के प्रति उस की विशेष जिम्मेदारी है।

हमें यह भी देखना चाहिए कि आखिर उन लोगों को पाकिस्तान से क्यों निकाला जा रहा है इस लिए कि वे हिन्दू हैं। उन का और कोई कुसूर नहीं है। हमें यह बात मान लेनी चाहिए।

मैं देश के एक बहुत बड़े व्यक्ति को बचोट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है :

"We agreed to the constitution of Pakistan by the partition of India because of a variety of things that had happened previously. We did not accept it at any time on the basis of a two nation theory. It was clearly understood that those communities which became the minority communities on this side or that must have the fullest protection and fullest

security for their lives. Otherwise, the whole structure which we have built up collapses, loses its basis."

यह किस का कहना है ? किसी जनसंघी का नहीं। यह बात हमारे देश के पहले प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू, ने कही है। उन्होंने कहा है कि अगर माइनारिटीज को प्रोटेक्शन नहीं दी जाती है, तो पार्टीशन का आधार खत्म हो जाएगा। चूंकि पाकिस्तान ने अपने वहाँ की माइनारिटीज को प्रोटेक्शन नहीं दी है, इस लिए पार्टीशन का यह आधार खत्म हो गया है। लेकिन हमारे मंत्री अपनी मजबूरी जाहिर कर के देश का अपमान कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हम सिवाये रिमाइंडर्ज भेजने के कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या हिन्दुस्तान में इस तरह की इम्पोटेंट सरकार बने रहने लायक है, जो देश, जाति और समाज का अपमान करती है ? हमारे देश के नेताओं ने पार्टीशन के समय जो कुछ कहा था, उन की तरफ से आखें मूंद कर वह अपने ढंग की कहानियां कहने लगती है। मेरा कहना यह है कि पाकिस्तान में रहने वाली माइनारिटीज का आप वाकी और इंडियन श्रीरिजिन के जो दूसरे देशों में लोग रहते हैं उन के साथ मुकाबिला नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, हमारे नेताओं ने, जवाहर लाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने उस समय जो हिन्दू वहाँ रह रहे थे पाकिस्तान में या ईस्ट बंगाल में उन के लिए कहा कि वह वहाँ बैठे रहें हम उन की जिम्मेदारी लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं फिर कोट कर रहा हूँ पंडित जवाहरलाल जी को :

"Therefore, it comes to this. We owe it to these people in East Bengal who may be endangered to give them protection in their territory, if there is no other alternative in their own territory, if circumstance demand it."

जवाहर लाल जी ने कहा कि अगर उन की प्रोटेक्शन नहीं होगी तो हम वहाँ जा कर के

उन की प्रोटेक्शन करेंगे। यह जवाहर लाल जी का कहना है। आज वह लोग, वह माताएं, वह बहनें जिन की वेइज्जती हो रही है, जो आज नंगे बगैर कपड़े के लाखों की तादाद में वहाँ से आ रहे हैं, वह मांग कर रहे हैं कि जवाहर लाल जी ने यह कहा था 20 वर्ष पहले। क्या यह सरकार, उन की बेटी की सरकार भ्राज सी रही है और उस के मंत्री यह कहते हैं कि सिवाय इस के कि हम रिमाइंडर दे दें और क्या कर सकते हैं ? क्या आप ने जो वादे किये थे उस से विपरीत काम नहीं कर रहे हैं ? मेरा कहना यह है कि भ्राज जो पार्टीशन का आधार है वह खत्म हो गया है और सरकार की जिम्मेदारी है, उसे कुछ कदम उठाना चाहिये। क्या कदम उठाने चाहिए, मैं यह कहता नहीं हूँ। मंत्री महोदय कहेंगे कि यह तो जंगी लोग हैं, लड़ाकू लोग हैं.....

बैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :
आप कहिये, खुलकर जो कहना है।

श्री कंबर लाल गुप्त : हां, मैं खुलकर कहूंगा। मैं आपको याद दिला रहा हूँ जवाहर लाल जी की बात कि जिस समय यह भगड़ा पहले भी हुआ 1950 में तो जवाहर लाल जी ने कहा था कि हमें दूसरे रास्ते भी अख्त्यार करने पड़ेंगे और जब उन्होंने कहा कि दूसरे रास्ते अख्त्यार करने पड़ेंगे तो तब लियाकत अली खां वहाँ से दौड़ कर आया, सात दिन यहाँ रहा और फिर उसने पंश्ट किया। आपके अन्दर कुछ दम होना चाहिए। आपकी पालिसी की जो इन्कासिस्टेंसी है, सेल्फ-कॉन्ट्रिबुशन है, क्या 22 साल में आपने उन्हें पहचाना नहीं ? क्या आप नई असेसमेंट करने चले हैं ? क्या आपकी इंटेलिजेंस, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर ने सब ले ली, लेकिन जो कुछ भी बची है, क्या उसके द्वारा आप दोबारा असेसमेंट करना चाहते हैं ? आज तक 22 साल में तीन प्रधान मंत्रियों में असेसमेंट कर लिया। क्या एक

[श्री कंवरलाल गुप्त]

ऐग्रीमेंट को भी पाकिस्तान ने माना है पूरी तरह से? 22 साल में कोई ऐग्रीमेंट भी उसने पूरे तौर से नहीं माना और आज आप कहते हैं कि हम देख रहे हैं कि वह मानेंगे या नहीं मानेंगे। वह तो मानने वाले नहीं हैं। अब हम यह देखना चाहते हैं कि वह नहीं मानते तो आप क्या करते हैं? जवाहर लाल जी ने कहा कि दूसरे रास्ते अख्यार करने पड़ेंगे। आप पूछेंगे वह दूसरे रास्ते कौन हैं तो मैं तो उनकी बात कहूंगा। लेकिन वह रास्ते कब आयेंगे? क्या आप कोई एकोनामिक ऐक्शन करेंगे? क्या कोई डिप्लोमेटिक ... (व्यवधान) ... मैं यह मानता हूँ कि लड़ाई अच्छी चीज नहीं है। मैं यह मानता हूँ कि आपस की बातचीत से कोई रास्ता निकल सकता हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं उसका स्वागत करता हूँ। कोई भी शांति प्रिय व्यक्ति इसका स्वागत करेगा कि कान्फ्रेंस टेबल पर बैठ कर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन यह एकतरफा बात नहीं हो सकती। जब तक दोनों पार्टियाँ इसके लिए तैयार नहीं होंगी आप तब तक बातचीत नहीं कर सकते। पाकिस्तान आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है और पाकिस्तान ने तो कहा कि हमारी तो गलती ही नहीं है। पाकिस्तान सरकार से आप बात कर रहे हैं फरक्का पर। मेरा यह कहना है कि आप पीस-मील टाक मत करिए। जो पाकिस्तान को ठीक लगे वहाँ तो वह कान्फ्रेंस टेबल पर आ कर बैठे और जो उसके विपरीत पड़ने की प्राशंका हो वहाँ वह बात न करे और आप यह कह कर के जितने भगड़े निपटते हैं वह अच्छी बात है, जो उनको देना है वह देते चले जायें और जहाँ आपको लेने की बात आए वहाँ वह बात करने को तैयार नहीं है तो पहले तो यह स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आप एक पैकेज डील करेंगे। मेरा पहला कहना यह है कि आप पीसमील ऐग्रीमेंट मत करिए। एक पैकेज डील होना चाहिए और सारी जो

समस्याएँ हैं उन समस्याओं पर या तो पाकिस्तान बात करना चाहता है तो करे और नहीं करना चाहता है तो आप कहिए कि हम भी बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। यह नहीं कि आप फरक्का पर तो बात करेंगे और जो हमारे भाई शरणार्थी आए हैं उनके बारे में बात नहीं करेंगे। यह बात नहीं चल सकती।

एक इन्कान्स्टेंसी शीर है। मैं प्रछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है या दुश्मन है? आप कहेंगे कि दोस्त तो नहीं है लेकिन दुश्मन भी नहीं कह सकते? क्यों नहीं जब वह इस प्रकार का व्यवहार करता है, हमारी अरबों रुपये की जायदाद ज्वत कर के उस ने नीलाम कर दिया हमारे जितने ऐग्रीमेंट है, किसी चीज को माना नहीं, वहाँ के लोगो को वह धकेल रहा है और इस के बाद भी यह सरकार कहती है कि हम उनसे बात करने के लिय तैयार हैं, वह हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं यह हमें मालूम नहीं, आखिर इस बेश को मालूम होना चाहिए कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। तो यह आप उन कोवता दीजिए कि अगर वह हम से बात करना चाहते हैं तो हम उन का स्वागत करने के लिय तैयार हैं। यह आप के लेवल पर बात नहीं हो सकती। यह इतनी बड़ी राष्ट्रीय समस्या है, प्रधान मंत्री को सोना नहीं चाहिए। सुबह और शाम बेकार की कहानियाँ कहीं चाँदनी चौक में, कहीं बंगाल में, कहीं दुसरी जगह तोता मना की तरह रटती रहती हैं और जो समस्या सामने है उस की तरफ उन का ध्यान ही नहीं है। उन के पास कैम्प में जाने के लिय समय नहीं है और कहती है कि मैं नहीं जा सकती। मेरा कहना यह है कि सारी बातों को छोड़ कर इस बात को प्रायोरिटी देना चाहिए। यह नेशनल प्रबलम है। प्रधान मंत्री को लिखना चाहिए कि आप आइए बात करने के लिए या मैं जाती हूँ बात करने के लिए। अगर यह बात करने के लिए तैयार नहीं है

विदिन ए वीक तो उन से कहिए कि हम आप से बात नहीं करेंगे, न फरक्का पर बात करेंगे, न और किसी चीज पर बात करेंगे और यह बता देना चाहिए कि यह हमारा फ्रैंडली कंट्री नहीं है, यह होस्टाइल कंट्री है ताकि देश को यह पता लगे कि यह होस्टाइल कंट्री है, दुनिया को पता लगे कि हिन्दुस्तान का यह मत है। लेकिन कहीं दोस्त है, कहीं दुश्मन है, यह जो गरम सरद चीज चलती रहती है इस से न देश में कोई महारत पैदा होती है और न आप में कोई जान पड़ती है। तो मेरा कहना यह है कि कोई एक कांस्टिटेसी पैदा कीजिए। मैं यह कहता हूँ कि आप यह करिए कि आप प्रेशर डालिए एकोनोमिक और डिप्लो-मेटिक और दूसरी चीज—मेरा कहना यह है कि आप इस समस्या को अन्डर-प्ले मत करिए। आप इस समस्या को अन्डर-प्ले कर रहे हैं, उस को बहुत छोटा कर रहे हैं। यह समस्या बहुत बड़ी है। यह दुख की बात है कि प्रधान मंत्री जी ने आज तक इस का कभी जिक्र भी नहीं किया। मुझे आप कहेंगे और अभी आप ने कहा कि आप तो लड़ाई की बात कहते हैं तो कहिए.....

श्री स्वर्ण सिंह : यह मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि खुल कर बात करिए।

श्री कंबर लाल गुप्त : मैं लड़ाई की बात नहीं करता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ।(व्यवधान).... मैं एक और महापुरुष को कोट कर रहा हूँ। जब इसी प्रकार से पूर्वी बंगाल का सवाल आया तो उन्होंने यह कहा :

"He said in one of his prayer speeches a few weeks before his death quite clearly that he hated war. But he said that these minorities are protected in India and they have been generally protected during the last two and a half years after the Delhi tragedies were over, and if the

minorities in East Bengal are not protected, he said, "Let the Government of India take action." He hated individual retaliation. He said that if the Government of India declares war on Pakistan, on that basis only he would not take part, but he would certainly bless such a step."

सभापति जी, यह महात्मा जी ने कहा था। किस के लिये कहा था? पूर्वी बंगाल से जो हमारे भाई जा रहे थे, उनके लिये कहा था। अगर पाकिस्तान वाले उन हिन्दुओं की रक्षा नहीं कर सकते, तो उन के लिये अगर गर्वनमेंट आफ इण्डिया को लड़ाई भी करनी पड़े, तो मेरा आर्शावाद होगा.....

श्री स्वर्ण सिंह : आपका आर्शावाद भी होगा।

श्री कंबर लाल गुप्त : मेरा तो है ही।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : सभापति महोदय, मेरी राय है कि मंत्री महोदय को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिये। गांधी जी ने कहा था कि मेरा आर्शावाद होगा—मंत्री महोदय इस को इतना हल्के रूप में ले रहे हैं, गांधी जी को गुप्ता जी के साथ तराजू में तोल रहे हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : यह बिल्कुल ठीक है, मुझ से गलती हो गई है कि मैंने आप को उन के साथ मिलाया।

श्री कंबर लाल गुप्त : ठीक है, इस बात को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिये। मैं तो गांधी जी को कोट कर रहा था।

मैं कह रहा था कि आज की पीढ़ी के सब से बड़े विद्वान और महापुरुष ने जब इस समस्या को हल करने के लिये यह रास्ता निकाला कि उस के लिये वे आर्शावाद देने के लिये तैयार थे, तो आज की सरकार यह कहती

[श्री कंबर लाल गुप्त]

है कि हम सिवाय रिमाइन्डर्ज के और क्या कर सकते हैं। आप उन को कहिये कि हम बात करना चाहते हैं, हमारे साथ बात कीजिये और अगर वह बात नहीं करना चाहते हैं तो आप कहिये..... मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारे देश में जो माइनीरिटीज रहती हैं उन की रक्षा की पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, बगैर किसी राजनीतिक भेदभाव के, बगैर किसी जातीय भेदभाव के हर एक व्यक्ति का यह धर्म है कि हमारे देश में रहने वाले किसी भी माइनीरिटी के व्यक्ति का, चाहे उस का कुछ भी धर्म हो, बाल भी बांका नहीं होना चाहिये। अगर हम यह व्यवस्था कर लें तो उस के बाद हमारे यहां रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का—चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान—यह फर्ज हो जाता है कि पाकिस्तान को बता दे कि आप जिन लाखों लोगों को खदेड़ रहे हैं, इस का हमारे देश की इकानमी पर असर पड़ेगा, ला-एण्ड-आर्डर पर भी इस का असर हो सकता है, आप को उस के लिये पैसा देना होगा, आप को उस के लिये जमीन देनी पड़ेगी।

कल मंत्री महोदय ने कहा कि हम जमीन मांगने के हक में नहीं हैं, इस से कम्पलीकेशन पैदा होगी। कम्पलीकेशन तो हमेशा पैदा होगी, आप जितना लड़ाई से डरते हैं, लड़ाई उतनी ही नजदीक आती जाती है, लेकिन जितनी दृढ़ता से बात करेंगे, लड़ाई उतनी दूर भागेगी। आप हमेशा हाथ जोड़ते रहे, पिछले 20 सालों में दो बार पाकिस्तान ने आप पर आक्रमण किया। मैं पूछना चाहता हूँ क्या कोई और भी ऐसा देश है जिस पर 22 सालों में इतनी बार आक्रमण हुआ हो, जितना हिन्दुस्तान पर हुआ है। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि आप मजबूती से खलिये और कहिये कि जमीन मांगेंगे, जो पैसा खर्च होगा वह पैसा पाकिस्तान को देना होगा।

सभापति जी, आपको याद होगा चौबीस

परगने के अन्दर अभी हमारे माननीय मंत्री—श्री संजीवैया जी गये थे और उन्होंने 13 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि हमारी कैबिनेट के अन्दर यह फैसला किया जायगा कि पाकिस्तान के खिलाफ हम को क्या कार्यवाही करनी चाहिये। मेरे पास प्रेस कंट्रिब्यू मौजूद है। उन्होंने यह भी कहा था कि जमीन लेने के मामले पर भी उस में विचार होगा। मैं जानना चाहता हूँ—जब आपकी कैबिनेट का एक मंत्री यह बात कहता है और दूसरी तरफ आप के दूसरे मंत्री यह कहते हैं कि यह एबसर्ड बात है—दोनों का मेल कहां है।

मेरा एक सुझाव यह है कि आप ने कोसी-जिन साहब के दबाव से ताशकन्द समझौता किया था। शास्त्री जी उस समझौते को नहीं करना चाहते थे, लेकिन रूस के दबाव में आकर हमने कहा कि हम को समझौता करना चाहिये। अब कोसीजिन साहब कहां हैं? आज रूस और पाकिस्तान के अन्दर ज्यादा नजदीक का सम्बन्ध दिखाई देता है—क्या उन को हम इस के बारे में नहीं कह सकते। इस सम्बन्ध में आप ने ऐसा कौन सा साहित्य छपा है। आज हिन्दुस्तान में जरा सी चटना होती है, पाकिस्तान सारी दुनिया में बाबेला मचाता है उस का प्रचार करता है। आप की करतूतों का प्रचार सारी दुनिया में चल रहा है, लेकिन हमारे दूतावास सो रहे हैं, हमारी संरकार सो रही है। मैं जानता हूँ कि आप ने ऐसा कौन सा मंटी-रियल छपा है, कौन से आंकड़े दिये हैं, कौन सी तस्वीरें छपी हैं—जरा पालियामेंट के मेम्बरों को भी बता दीजिये। मैं चाहता हूँ कि सरकार जल्द से जल्द इस प्रकार का पूरा साहित्य छाप कर सारे देश के लोगों को अवगत कराये कि हमारे देश में क्या हो रहा है।

सभापति महोदय, मैं एकसचेन्ज आफ पापुलेशन के हक में नहीं हूँ। कई लोगों ने

कहा है कि एक्सचेन्ज ग्राफ पापुलेशन होना चाहिये। मैं इस का कट्टर विरोधी हूँ क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि जब हमारे देश ने इस एग्ज़िस्टेंट को मान लिया कि यहाँ की माइनीरिटी की जिम्मेदारी भारत सरकार की है तो उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से हमें निभाना होगा। इस लिये उस का यह हल नहीं होगा कि हम उन को यहाँ से खदेड़ दें, मेरी पार्टी इस विचारधारा को विरोधी है। माइनीरिटीज को ठीक तरह से रखने में ही हमारे हाथ मजबूत हो सकते हैं और हम दुनिया के सामने और यू० एन० ओ० के सामने सिर उठा कर खड़े हो सकते हैं। इस लिये, सभापति जी, मेरा यह कहना है कि सरकार को मजबूत होना चाहिये, इस के लिये जो कुछ भी कार्यवाही की जरूरत पड़े, उसे सरकार को करना चाहिये। लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान नहीं मानता है तो हमें डिप्लोमेटिक रिलेशन्स भी हटा देने चाहिये। आप कहते हैं कि बात करने का कोई रास्ता होना चाहिये। क्या रास्ता है? वहाँ आप के दूतावास को तो यह भी मालूम नहीं है कि पाकिस्तान ने दो आदमियों को फांसी पर लटकवा दिया है। अगर दूतावास बन्द हो जायगा तो उस से कोई लम्बा चौड़ा नुकसान होने वाला नहीं है, कम से कम पाकिस्तानी दूतावास यहाँ पर जो स्पाइंग करता है, वह तो बन्द हो जायगा—इस लिये जरूरी है कि आप कोई कड़ा स्टेप उठायें।

सभापति महोदय, इस सरकार ने उन आने वाले विस्थापितों को बसाने के लिये केवल 34 लाख रुपया रखा है। डेढ़ लाख के लगभग हमारे भाई अब तक आ चुके हैं और डेढ़ लाख और आने वाले हैं वारिशों के बाद। इस तरह से आप देखेंगे कि एक आदमी के पीछे केवल 8 रुपये आते हैं। हमारे कुछ साथी—श्री बेनी शंकर शर्मा और श्री जगन्नाथ राव जोशी अभी हाल में वहाँ गये थे। उन्होंने हमें बताया कि

वहाँ पर लोगों के रहने के बास्ते तम्बू भी नहीं हैं। जो तम्बू हैं उन के नीचे पानी बह रहा है, मँलेरिया फैल रहा है, उन के पास कपड़े नहीं है। मैं मांग करता हूँ कि पालियामेंट के मेम्बरों की एक कमेटी वहाँ देखने के लिये जाय, उन से बातचीत करे, वहाँ की स्थिति का जायजा लेकर बताये कि सरकार को क्या कार्यवाही करनी चाहिये। मैं यह भी चाहता हूँ कि वार-फूटिंग पर उन की रिहैबिलिटेशन का काम होना चाहिये। सब पार्टियों के सहयोग से अगर यह काम होगा तो मैं समझता हूँ कि अच्छा होगा। मैं यह मांग भी करूँगा कि प्रधान मंत्री स्वयं भी जल्द से जल्द वहाँ जा कर देखें। मंत्री महोदय ने जो रवैया अभी दिखलाया है—जैसे उन्होंने कहा है कि हम क्या कर सकते हैं—अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो जो कर सकते हैं उन के लिये जगह खाली कर दीजिये। मैं मांग करता हूँ कि जो कर सकते हैं, उन के लिये जगह खाली कर दीजिये। इस तरह के नाअहल और बेकार के स्टेटमेन्ट दे कर उन गरीब लोगों के जखमों पर, जो हमारे देश में आ रहे हैं, नमक मत छिड़किये। आप को जो कुछ जवाहर लाल नेहरू जी ने कहा, सरदार पटेल ने कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा, उस को मिट्टी में मिला रहे हैं, क्योंकि आप के अन्दर दम नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं और शान्ति-शान्ति के नाम पर अपने देश को लड़ाई के मुँह में धकेल रहे हैं। जितना शान्ति शान्ति करते जायेंगे उतना लड़ाई की तरफ जाते जायेंगे। मेरा कहना है कि हिम्मत कीजिये, शर्म कीजिये, सरदार पटेल की बात को याद कीजिये, महात्मा गांधी को याद कीजिये और देश के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़िये। आप को एक ब्राह्मण के साथ देश खड़ा होगा, तब फिर इस हमारे साथ रहता है या नहीं, अमरीका हमारे साथ रहता है या नहीं, हिन्दुस्तान को 50 करोड़ जनता अपनी किस्मत का

[श्री कंबर लाल गुप्त]

खुद फंसला कर सकती और उस हालत में पाकिस्तान बगैर लड़ाई के ठीक हो जायगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव रखता हूँ।

सभापति महोदय : इस पर 2 घण्टे का समय है, आधा घण्टा आपने ले लिया है। इस लिये प्रार्थना है कि जिन पार्टियों का जो भी समय है, उस में ही खत्म करें।

श्री कंबर लाल गुप्त : बिजनेस एडवाज़री कमेटी में स्पीकर साहब ने कहा था कि इस का समय बढ़ाया जायगा।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : सभापति महोदय, मैं आपसे विनती करूंगी कि यह विषय ऐसा महत्वपूर्ण है कि अगर जरूरत होगी तो आप थोड़ा समय बढ़ा दीजिएगा। इस सदन में बैठकर हम लोग बहुत सी बातें करते हैं, इतना समय बर्बाद जाता है लेकिन यह विषय ऐसा है कि इस पर अगर ठीक से बहस होगी तो देश का फायदा होगा। हम लोग इसके लिए ज्यादा देर तक बैठने के लिए तैयार हैं।

यहां पर जो बातें कंबर लाल जी ने कही हैं उनको दोहराऊंगी नहीं लेकिन मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि पूर्व बंगाल से यहां पर 55 लाख रेफ्यूजीज आ गये हैं, वे अगर एक दफा आते जैसे कि पश्चिम पाकिस्तान से आये हैं तो उनका एक पक्का इन्तजाम होता और वे बस जाते लेकिन बीस पच्चीस सालों से लगातार थोड़े थोड़े करके वे लोग आ रहे हैं। हमने समझा था कि किसी बरत उनका आना बन्द होगा लेकिन हर बरत कोई न कोई बहाना उनके आने का लगा रहता है। इस समय आज हम क्यों चर्चा कर रहे हैं ? इस लिए चर्चा कर रहे हैं कि

पिछले साल अक्टूबर महीने या उस से पहले से यह सिलसिला शुरू होता है। धीरे धीरे थोड़े थोड़े रिफ्यूजीज आ रहे हैं। 1958 तक काफी रिफ्यूजीज आये थे, फिर थोड़े दिन बन्द हुए। उस के बाद सन 1964 से आने शुरू हुए और थोड़े थोड़े आने लगे। सन 1969 से और बढ़े। मैं आप का ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि इस का कारण क्या है ? यस कोई मामूली कारण नहीं है। पाकिस्तान में जो पोलिटिकल प्रेशर्स है उनमें हिन्दू शिकार बनाये जा रहे हैं, उनको भगाया जा रहा है। अक्टूबर 1969 में क्या हुआ ? हिन्दुओं को शो काज नोटिस भेजी गई कि उनकी जायदाद क्यों न अटेच की जाये। यह क्यों भेजी गई ? वहां पर जो बड़े बड़े हिन्दू हैं उनको चार चार साल के लिए जेल भेजा गया और उनकी सारी की सारी जायदाद फीज की गई। अभी जो वहां से बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी नेता त्रैलोक्य महाराज जी आये हैं वे कहते हैं कि वहां पर नीयर एनाकिक कन्डीशन्स प्रिवेल कर रही हैं। जब से उन्होंने हिन्दुओं की जायदाद लेनी शुरू की है और हिन्दुओं की जायदाद लेने के लिए नया कानून बना है, वहां पर नीयर एनाकिक कन्डीशन्स हो रही हैं जिसमें हिन्दुओं का रहना नामुमकिन हो रहा है। यह वह लोग तो कर ही रहे हैं जोकि मुस्लिम जमाअतें हैं, कम्युनल टाइप के ग्रुप्स हैं लेकिन गवर्नमेंट भी कर रही है। जब से वहां पर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा भारी मोर्चा हिन्दुओं को निकालने का शुरू किया है तब से यह बात बढ़ गई है। मैं फोगर्स देकर आप का समय नहीं लेना चाहती। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो मालूम होगा कि हर महीने पहले से शुरू हुए और फिर हजारों से शुरू हुए। धीरे धीरे बढ़ते गए। अक्टूबर, 1969 से मास एग्जाडस शुरू होता है बुद्धिस्ट्स और हिन्दुओं का खुलना से। वनगांव जोकि बार्डर पर है और बसीरहाट तथा हसनाबाद में जिस हालत में रेफ्यूजीज हैं वह बदतर है जैसे कि जानवर रहते हैं। उस हालत में न उनके रहने के लिए, न

साने के लिए और न सेनिटेशन का कोई प्रबन्ध है। मिनिस्टर साहब जाकर देख आये हैं, उनको मालूम है। 24 परगना में प्रब्ले की रिपोर्ट है कि बीस हजार रेफ्यूजीज आ चुके हैं और इस तरह उनका हर महीने नम्बर बढ़ता चला जा रहा है। मई के महीने में जब यहां पर लोगों की परेशानी की रिपोर्ट आई पार्लमेंट में इस पर काफी बहस चली और मेम्बरान परेशानी का इजहार करने लगे तो उसके जवाब में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, श्री दिनेश सिंह ने कहा कि बिल्कुल लाचारी है। जहालतपने का इजहार किया। उन्होंने कहा :

Despite repeated attempts we have not been able to persuade the Pakistan Government to meet.

पाकिस्तान तो हमारा नेबरिंग कंट्री है और हम इतना बड़ा कंट्री है, प्राइम मिनिस्टर यहां पर शेर जैसी गर्जती हैं, मालूम होता है हिन्दुस्तान ही नहीं दुनिया की बड़ी भारी ताकत बनी हुई हैं लेकिन नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान से इतना भी नाता नहीं है कि एक मेज पर बैठ कर रेफ्यूजीज के बारे में बात चीत हो सके। हम लोग तो उनसे मिन्नत करें बात करने के लिए और वे हमको धक्का दे रहे हैं। हालत यह है कि अब और डेढ़ लाख रेफ्यूजीज आ चुके हैं और एक लाख 80 हजार आने के लिए तैयार बैठे हैं बाडर पर। चूंकि घनघोर बारिश हो रही है इसलिए उस तकलीफ में वे आ नहीं सकते हैं और जैसे ही बारिश खत्म हो जाएगी वे आ जायेंगे। दो हजार करके रोज आ रहे हैं मिजरेबिल हालत हैं।

लेकिन इसका कारण क्या है ? कारण यह है कि वहां पर चुनाव होने वाला है और राजनीतिक उथल पुथल चल रही है। वहां पर मुजीबुर्रहमान की पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी मानी जाती है और लोग समझ रहे हैं कि ईस्ट बंगाल के हिन्दू उस पार्टी को वोट देंगे इसलिए

हिन्दुओं को यहां से निकाल दो ताकि मुजीबुर्रहमान की पार्टी की ताकत कम हो जाये और वह न आ सके।

दूसरी बात यह है कि वेस्ट पाकिस्तान के मुकाबले में ईस्ट पाकिस्तान की पापुलेशन ज्यादा है। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, दोनों की ग्रापस में लड़ाई चलती है—वेस्ट पाकिस्तान चाहता है कि ईस्ट पाकिस्तान पर हुकूमत रखे और उसको ऊपर न आने दें लेकिन अगर चुनाव होगा तो चूंकि ईस्ट पाकिस्तान की पापुलेशन ज्यादा है इसलिए वे ऊपर आ सकते हैं तो फिर क्या किया जाये ? इसीलिए पाकिस्तान की सरकार चाहती है कि ईस्ट पाकिस्तान से हिन्दुओं को निकाल दो ताकि ईस्ट पाकिस्तान की पापुलेशन वेस्ट पाकिस्तान की पापुलेशन के मुकाबले में घट जाये। इसीलिए हिन्दुओं को वहां से भगाया जा रहा है।

इसके अलावा वहां पर उर्दू और बंगला जबार पर बड़ा झगडा चलता है। जो लोग पाकिस्तान में डामिनेट करते हैं उन्होंने पहले समझा था कि उर्दू जबान हम उन पर थोप देंगे लेकिन बंगालियों ने, चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान हों, अपनी मादरी जबान के प्रति प्रेम रखकर बड़ी घमासान लड़ाई लड़ी। इन सब कारणों से आज वहां पर बड़ी राजनीतिक उथल पुथल हो रही है। मुस्लिम लीग और जमायत उल उलमा जैसी जो कट्टर जमाअतें हैं उनके कारण वहां से हिन्दू निकाले जा रहे हैं। और यहां पर हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जब में हाथ डाल कर बैठी हुई है। ये कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं।

What can we do ? We have repeatedly requested but we cannot bring them round.

जहां तक रिहैबिलिटेशन का सवाल है, मैं मानती हूं कि इतने सालों में कुछ काम अच्छे

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

भी हुए हैं। अगर वे बार बार आते जायें तो क्या किया जाए। एक बार अगर पता चल जाये कि इतने लोगों को बसाना है तो उसका इन्तजाम कर दिया जाये लेकिन अगर रोज आते जायें तो उनके लिए पैसा और दूसरे साधन जुटाना मुश्किल होता है। लेकिन उसके बावजूद मैं मानती हूँ कि काम हुआ है लेकिन मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि जितना गवर्नमेंट को गीयर अप होना चाहिए था, जिस तरह से इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को मीट करना चाहिये था और जितना इन्तजाम करना चाहिए था, जिस तरह से वहाँ से हटाकर दूसरी जगह ले जाना चाहिए था वह नहीं हो रहा है। स्टेट्स को मदद करने के लिए कहा है लेकिन वह किस किस्म की मदद है वह मालूम नहीं है।

मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ जिसमें कि मेरा निजी तर्जुबा है। 25 तारीख को मैं बनारस में एक अनअटेंड ओल्ड वीमें कॅम्प देखने गई थी। वहाँ की एक बहन बर्कर हैं जोकि हमारी पार्टी की नहीं हैं, मेरी पुरानी साथी थीं लेकिन आजकल इन्दिरा गांधी की पार्टी की हैं। वह मुझे ले गई। मैं बता नहीं सकती, मैं वहाँ की हालत देखकर थर्रा गई। उस तरह के मकान में म्युनिसिपैलिटी किसी कुत्ते को भी नहीं रहने देगी। दीवारें टूटी हुई हैं और पत्थर छत से गिरने लगे हैं और उसके नीचे बुढ़ियायें पड़ी हुई हैं जमीन पर। खाना पकाने के लिए बर्तन देने के लिए सरकार ने कुछ पैसा मंजूर किया है। लेकिन उसको लोग चोरी करके खा जाते हैं। उनके पास लोटे जैसे छोटे छोटे बर्तन हैं जिनमें चावल भी नहीं पकाये जा सकते। मिट्टी के बर्तनों में पका कर खाते हैं। इसी तरह से खुराक के लिए जो 22 या 23 रुपये दिये जाते हैं उसमें नोकर का पैसा काट लिया जाता है और दो दो नोकर इंस्पेक्टर वगैरह के घरों में काम करते हैं। जो बीमार हैं उनके लिए दवाई

का पूरा इन्तजाम नहीं है। यह देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मेरी जब मैं सी रुपये थे, मैंने वह निकाल कर दे दिए और कहा कि जिनके लिए दवाई की जरूरत है उनको दीजिए और मैं दिल्ली जाकर और पैसा भेजूंगी। पहले मैंने यहाँ पर श्रीमती फूलरेणु गुह से कहा था कि इसका कुछ इन्तजाम होना चाहिए तो उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ, स्टेट गवर्नमेंट करती हैं। मैंने स्टेट गवर्नमेंट को लिखा था और मैं कहूंगी कि मेरे कहने पर मिनिस्टर साहब ने किसी को इन्सपेक्ट करने के लिए वहाँ पर भेजा। लेकिन आज भी हालत वही है। अब जो नये लोग आये हैं उन के सिलसिले में मैं कहना चाहती हूँ कि माना कॅम्प में जो लोग हैं उनको इस छत के नीचे मरने के लिए भेज दिया गया है। आज कुत्तों की भी जिन्दगी उतनी खराब नहीं होगी जितनी खराब जिन्दगी उन लोगों की है। मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी को चैलेन्ज करती हूँ, जिनके घर के सामने गरीबों का तांता रहता है, जो आज गरीबों की लीडर बनी हुई हैं, कि जरा वहाँ जा कर देखें कि उन के राज्य में किस तरीके से उन लोगों को रक्खा गया है। किसी इन्सान को वहाँ नहीं रक्खा जा सकता है, लेकिन बड़े से बड़े लोगों को वहाँ पर रक्खा गया है जिन पर तरह तरह के अत्याचार होते हैं। ऐसी हालत में वे लोग पड़े हुए हैं। इस लिए हम को फौरन इस का प्रबन्ध करना चाहिए। अगर प्रधान मंत्री उन की मदद न कर सकें तो हम लोग इस के लिए चन्दा कर के इन्तजाम करें।

जैसा मैंने कहा यह काम केवल रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री से नहीं होगा, एबस्टर्नल अफेअर्स मिनिस्ट्री का भी पैनलेल टास्क है। जैसा श्री गुप्त ने अभी कहा पाकिस्तान पर जोर डाल कर नेहरू लियाकत पैकट पर अमल कराने की फोशिया करनी चाहिये। जब तक हम कुछ इस तरह की बात नहीं करेंगे तब तक वह लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे। पाकिस्तान वालों ने डांट कर एक नोट भेजा और कहा कि

आप लोग झूठ बोल रहे हैं, मैलिक्सा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो लोग वहां से आये हैं उन के बारे में एग्जरेट कर रहे हैं। यह तो उल्टा चोर कोतवाल को डाटे वाली बात हो गई। वहां से लोग आ रहे हैं उन का कोई प्रबन्ध वह लोग करते नहीं और हम से कहते हैं कि हम झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। हमारी सरकार इस पर भी चुप बंठी है। उन को कोई फिक्र नहीं है, जो चाहे हम को गाली दे, लेकिन हम इतनी बड़ी स्टेट होने के फल में मर रहे हैं और अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते।

आज या कल जवाब देते वक्त श्री स्वर्ण सिंह ने कहा था कि हम देश के लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन मंडम बिन के यहां आने का नतीजा आप ने देख लिया। अखबार में आया है कि सैगान में यहां के लोगों की क्या हालत हो रही है। आप ने देख लिया कि एक बड़े बिजनेसमैन ने हांगकांग में क्या स्टेटमेंट किया है आप उनका स्टेटमेंट पढ़िये। यह कहते हैं, हरी लाला वहां के बड़े भारी मर्चेंट हैं जो सारे हिन्दुस्तान के मर्चेंट्स के प्रेजिडेंट हैं, वह कहते हैं कि हिन्दुस्तानियों का वहां रहना नामुमकिन है, नहीं तो इस का कोई हल निकाला जाये। आज हिन्दुस्तानियों को सीलोन से निकाला जा रहा है। सीलोन वाले यहां आये हुए हैं, उन से बात की जाये। आज पाकिस्तान से निकाला जा रहा है, बर्मा से निकाला जा रहा है। हमारा देश बड़ा शक्तिशाली है, लेकिन हमारी फारेन पालिसी का नतीजा यह है कि we have no friends. Nobody is trying to help us. Nobody is trying to support us.

अपने घमण्ड के कारण इतने आइसोलेशन में पड़े हुए हैं कि कोई काम कर नहीं सकते, किसी को मदद नहीं दे सकते। मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेहरबानी कर के जरा इस पर ध्यान दीजिये।

आज हम को उन हिन्दुस्तानियों के लिए कोशिश करनी चाहिये जिन की मुसीबतों के

लिए हम जिम्मेदार हैं। आज उन की जो हालत है उस के लिए हम जिम्मेदार हैं। अगर हम मुल्क का पार्टिशन कबूल न करते तो वह लोग अपने घरों में अमन चैन से बैठे होते। आज वह लोग मिखारियों की तरह से दर दर घूम रहे हैं। उन को रखना, उन को सुरक्षा देना, उनको खिलाना पिलाना हमारा काम है। मैं भी उन के साथ डिमान्ड करती हूँ कि एक कमेटी पार्लियामेंट मेम्बरों की खर्बाई जाय जो बसीरहाट जाय, हसनाबाद जाये और उन कैम्पों को देखे कि वह लोग किस हालत में हैं। फौरन और खर्चों का पैसा काटे फारेन ट्रिप्स से पैसा काटे और उन को दे जो लोग हमारे पास आये हैं। हम उन को प्रोटेक्शन दें और वह जिस तरह से रहना चाहें, वैसे रह सकें ऐसा प्रबन्ध करें।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, जो मोशन 193 की तहत हाउस के सामने आया है और जो हर रोज के हालात हम अखबारों में पढ़ते हैं उन से मलूम होता है कि यह एक बड़ी गम्भीर समस्या है और हम को इस पर निहायत संजीदगी से सोचना है। यह बात नहीं है कि हाउस के सामने कोई प्रस्ताव आये तो हम उस को लाइट-हाटेड श्री लेते हैं।

जब हिन्दुस्तान का बटवारा हुआ तब उस वक्त भी कई बुनियादी बातें तय हुई थीं। यह कहा गया कि तुम लोग अलग नेशन हो। महात्मा गांधी ने उसे नहीं माना, लेकिन पाकिस्तान बना अलग। कहा गया कि हिन्दुस्तान के लोग अलग हैं। वह अलग रहें और हम अलग रहे। लेकिन बुनियादी बात यही तह हुई थी कि पाकिस्तान में जो अकलियतें हैं उन को कोई तकलीफ नहीं होगी। हिन्दुस्तान में भी यह करार पाया गया कि यहां भी जितनी अकलियतें हैं उन भाइयों को कोई तकलीफ नहीं होगी।

[श्री रणधीर सिंह]

दोनों देशों के दरम्यान बुनियादी तौर पर आपस में नफ़त रही, झगड़े रहे। कई पाकिस्तान से भगड़े हुए। कभी पानी का झगड़ा कभी असम पर झगड़ा हुआ। दूसरी बातों में भी भगड़े हुए। बहुत से लोग उधर से इधर आये और इधर से उधर गये। बजाय इस के उन भगड़ों का ख़ात्मा होता मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। जहाँ तक हमारा सवाल है हमें फ़ख़ है इस बात का कि हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट और सभी हिन्दुस्तान के वासी यहाँ पर जितनी भी अकलियतें हैं उन के बारे में नेहरू लियामकत ऐक्ट जो हुआ उस के पाबन्द हैं।

यह बात ठीक है कि यहाँ भी कुछ इक्के दुक्के ऐसी बातें हुईं जिन से हम खुश नहीं हैं। उन से हमारे मुल्क का नाम बाहर बदनाम हुआ, हम पर हर्ष आया और हमारे माथे पर धब्बा लगा, लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वह निहायत शर्मनाक है, और इस के लिये पाकिस्तान जिम्मेदार है। इंटरनेशनल जिम्मेदारी पाकिस्तान की है बतौर एक मुल्क के बतौर एक क़ौम है। वह सुखरू हो कर निकले इस बात से कि अगर हम कोई बात कहें तो वह सटपटाये नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी महसूस करे। पंडित जी ने यह बात कही थी, गांधी जी ने यह बात कही थी। लेकिन अगर आपस में हालत यही रहती है और उस मुल्क में जितनी अकलियतें हैं वह पाकिस्तान से निकाल दी जाये तो यह सही बात है कि तकसीम की बुनियाद ही नहीं रहती। इस में कोई शक नहीं है कि हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी अकलियतों को बचायें, लेकिन इस नाते से नहीं कि हम हिन्दू हैं इस लिए हिन्दुओं को बचायें। पाकिस्तान में जो लोग बसते हैं अकलियतों के, उन में हिन्दुओं के अलावा ईसाई भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, जिन के साथ कभी हमारा खून का रिश्ता हुआ करता था। अभी भी वहाँ के हुक्काम अलग हैं लेकिन वहाँ की जनता जोर

हिन्दुस्तान की जनता में प्यार होना चाहिये। प्यार था, अभी भी प्यार है और आगे हो कर रहेगा। लेकिन वहाँ नफ़त पैदा की जाती है, एक तबके का जेनोसाइड किया जा रहा है, इस में कोई शक की बात नहीं है।

यह बात नहीं है कि हम अपनी डफ़ली पीटना चाहते हैं जिसमें यह समझा जाय कि यह कोई पार्टी की चीज है, यह नेशन का सवाल है, मुल्क का सवाल है। अगर कोई कांटा लगता है इधर से उन भाइयों के जो बीस साल पहले हमारा हिस्सा थे और अब भी हैं, अगर कोई रंजिश होती है तो हमें उन के साथ हमदर्दी होती है। मैं कतअन इस बात से इत्फ़ाक नहीं करता कि कोई ऐसी बात कही जाय जिस से पाकिस्तान का हौसला बढ़े। हमें डिप्लोमैटिक तौर पर भी और उससे आगे और जो फ़ौरम हों उन में मजबूती से इस मसले को हल करना चाहिये। मैं उन आदमियों में से हूँ जो महसूस करते हैं कि पाकिस्तान कतअन डिप्लोमैसी और आम नेगोशिएशनस की बातों को नहीं मानेगा। अगर पाकिस्तान से डिसेंट तरीके से, शराफ़त से बात की जाय तो वहाँ की हकूमत सुनती नहीं है, हम बीस साल से देख रहे हैं कि पाकिस्तान हमारी बात नहीं मानता। अगर उस से थोड़ा सा दूसरे तरीके से कहा जाय कि यह खुदार आदमी हैं और तुम इन को बहका नहीं सकते और जो तुम्हारे यह तरीके हैं इन के नतायज खराब हो सकते हैं, तो वह उस को समझेंगे।

मैं आप की माफ़त सरदार साहब से कहना चाहूँगा, वह मजबूत आदमी हैं, मजबूत तबके से ताल्लुक रखते हैं, मजबूत स्टेट से आये हैं, इस लिये कहना चाहूँगा कि वह थोड़ा सा मजबूत बनें। हर जगह पर कमजोरी से बात तय नहीं हुआ करती। यह कोई 100, 200 या 400 आदमियों का सवाल नहीं है, यह तादाद लाखों में बढ़ती जा रही है और अगर

यही पालिसी रही तो और भी बढ़ती जायेगी । आप कहेंगे कि हम करें क्या ? यह बात मैं आप पर छोड़ता हूँ । मैं कोई जंगवास नहीं हूँ कि आपस में लड़ाने की बात कहूँ, लेकिन जो जैसा मरीज हो उस का वैसा ही इलाज होना चाहिये । पाकिस्तान के कान आप को खोलने चाहिये, और अगर उस के कान नहीं खुलते तो पाकिस्तान के दोस्तों की मार्फत उस के कान खोलें जायें । अगर उस तरह से भी नहीं खुलते तो फिर कांफरेंस के जरिये उस के कान खोलें । क्या घट जायेगा, कौन सी बेइज्जती होती है अगर आप वहाँ के फारेन मिनिस्टर को यहाँ बुलायें या आप वहाँ तशरीफ ले जायें या डिप्लोमैटिक तौर पे सेक्रेट्रीज की कांफरेंस हो । मैं मानता हूँ कि दूसरी डिस्प्यूट भी हैं जिन को हल करना है, लेकिन यह एक ऐसी चीज है जो दोनों मुल्कों के लोगों के दिलों पर नासूर का काम करती है । जिन बातों को आदमी इतना महसूस करते हैं उन को हम छोड़ते जायें और छोटी बातों को जो उन को मीठी लगे पूरा करते जायें तो फिर हमारे मसले कभी हल नहीं होंगे । अगर हम काश्मीर का सवाल अगुआ रखते हैं तो यह एक कमजोर पालिसी है । यह कमजोरी की पालिसी है । इसको छोड़ना होगा । मैं पूरे जोर से कहना चाहता हूँ कि इस सवाल को ह्यूमन राइट्स कमिशन में उठाया जा सकता है, यू०एन०ओ० में उठाया जा सकता है । मैं जानता हूँ कि इसके इम्प्ली-केशन हो सकते हैं । आप उनको अच्छी तरह से जानते भी होंगे । लेकिन आप देखें कि क्या पाकिस्तान हमें कभी किसी भी मामलेपर बख्शता है ? जहाँ कोई बात होती है, वहाँ काश्मीर की बात को उठा देता है । इस्लामी सम्मिट में इस बात को वह ले जाता है । वहाँ पर इसको उठा देता है । और भी कोई मंच होता है तो वहाँ सवाल को वह उठा लेता है । यू० एन० ओ० में इसको ले जा कर वहाँ इसको उठा लेता है । इस तरह की कई बातें वह करता है ।

यह देश बहादुरों का देश है । मैं चाहता हूँ कि मजबूती के साथ, बहादुरी के साथ इस देश के साथ इस देश के 55 करोड़ लोगों को आवाज उठानी चाहिये । मुझे खुशी है कि इस मामले में वे एक हैं । इस मसले को लेकर एक पार्लिमेंटरी इंडीगेशन भी सरकार को पाकिस्तान भेजना चाहिये जो वहाँ जा कर फर्स्ट हैंड नालेज लें । अगर पाकिस्तान इससे इन्कार करता है तो फिर उसी सतह पर उन से सरकार को डील करना चाहिये, उसी भाषा में उसके साथ बात होनी चाहिये । मैं बिला दरेग कहना चाहता हूँ कि आने वाले जो लोग हैं, उन पर आप किसी तरह की रोक न लगाएँ । लेकिन आप देखें कि एक तरफ तो असम की आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है, वहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग आ कर रह रहे हैं और आ कर वहाँ के रेशों प्रोपोर्शन को बिगाड़ रहे हैं, असम आबादी बिगाड़ रहे हैं और दूसरी तरफ इन लोगों को हिन्दुस्तान में धकेला जा रहा है । यह जो सब चीज है इस में दाल में काला जरूर है । इसको बरदाश्त नहीं किया जा सकता है । इसके पीछे कोई साजिश है । डिप्लोमेसी का यह तकाजा है कि नहले पर दहला हम मारें । ऐसा नहीं होना चाहिये कि वे लोग तो ऊट पटांग करते रहें और हम भेड़ बकरियों की तरह बँठे देखते रहें और हर चीज को बरदाश्त करते रहें । सिआसत में शुजाअत से, बहादुरी से, हिम्मत से काम होता है । हैशजाअत मर्दें मँदाने सियासत की भ्रमा । आप तकड़ेपन से कहेंगे तब वह आपकी बात को सुनेगा । तकड़ेपन से मेरा मतलब यह नहीं है कि आप उसके खिलाफ लड़ाई छेड़ दें । लड़ाई की बात मैं नहीं कहता हूँ । लेकिन राजनीति में अगर आप तकड़े हो कर, सस्ती से कोई बात कहते हैं तो उसका असर सारे देशों पर होता है । पाकिस्तान के और हमारे भी जो दोस्त मुल्क हैं, उन के जरिये आप बात उसके सामने रखें । मलेशिया आपका दोस्त है, नासर आपका दोस्त है, अफगानिस्तान हमारा बेहतरीन दोस्त है ।

[श्री रणधीर सिंह]

ईरान हमारा दोस्त है, उनमें से किसी की मार्फत इस मामले को उठाया जा सकता है। अगर उसको किसी एक मामले में एक फीसदी भी नुकसान होता है तो उस नुकसान को ले कर वह हमें सारी दुनिया में बदनाम करता फिरता है लेकिन दूसरी तरफ हम हैं कि लाखों जानों का सवाल भी होता है तो उसकी बाज़त भी हम टस से मस नहीं होते हैं। हम कुछ करते तो हैं लेकिन थोड़ा करते हैं। हम को कमजोरी नहीं दिखानी चाहिये इस मामले में।

एक और बात हमारी बहन श्रीमती कृपलानी ने कही है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम एक इमेज पेश करें। लेकिन क्या वजह है कि हर जगह जहाँ कहीं हिन्दुस्तानी गए हैं, ठोकरें खाते फिरते हैं, उनको ठोकरें मारी जाती हैं। अफ्रीका में, केनिया में, हमारे लोगों की यही हालत है। बर्मा में भी कोई उनकी खुशगवार हालत नहीं है। लंका में भी हीसला अफजा बात नहीं है। जहाँ कहीं हमारे लोग जाते हैं ठोकरे खाते हैं। इस सब का क्या मतलब है? हमारी कीम एक बड़ी मजबूत कीम है। दुनिया में हमारे देश की आबादी दूसरे नम्बर पर है। किस बात की कमी है हम में? कोई कमी नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि हिन्दुस्तानी नस्ल के भ्रादमी चाहे दुनिया के किसी देश में हों, वहाँ उनके साथ इस तरह का सलूक हो। हिन्दुस्तानी इस्लामी मुल्कों में हैं। दूसरे मुल्कों में हैं। वे ईराक में हैं, बड़ी अच्छी इज्जत उनकी वहाँ होती है। मिश्र में उनकी बड़ी इज्जत होती है। ईरान में होती है। अफगानिस्तान में होती है। वजह क्या है कि अकेले पाकिस्तान में हिन्दुस्तानी डीसेट के लोगों को फांसी चढ़ाया जाता है? हो सकता है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी यह हो कि हम को बदनाम किया जाए और अपना उल्लू सीधा किया जाए। यह भी हो सकता है जैसा कि श्रीमती कृपलानी ने कहा है कि वहाँ जो ईस्ट और वैस्ट पाकिस्तान में भगड़े चल रहे हैं उस

सिलसिले में इन लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा हो। यह भी हो सकता है कि अपने अन्दरूनी मसलों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा हो। इस वास्ते मैं कहना चाहता हूँ कि इस मामले में आपको सख्त कदम उठाने चाहिये।

अब सवाल पैदा होता है कि यह समस्या हल कैसे हो। मैं नहीं समझता हूँ कि तबादला इसका कोई हल हो सकता है। बलकान में लाख के करीब आदमी इधर से उधर घाना चाहते थे, वह नहीं हुआ। तबादला कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बीस लाख इजराइल के यहूदियों ने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया है। यहाँ तो डेढ़ करोड़ आदिमियों का सवाल है। कोई छोटी बात नहीं है। मैं इसको फिरकापरस्ती के नज़रिये से नहीं कहता हूँ। बीस लाख लोगों ने पब्लिक ओपिनियन दुनिया में पैदा की। क्या डेढ़ करोड़ आदमी दर बंदर की ठोकरें खाते फिरेंगे? क्या उन के वास्ते कोई सिलसिला नहीं बनेगा? एक भाई ने कहा कि उनके लिए टेरिटरी की मांग की जाए। मैं समझता हूँ कि एक वक्त आएगा जब दोनों टेरिटरीज एक होंगी। आपस में हाकिम लोग आपस में लड़ते हैं, जनता नहीं लड़ती है। जनता एक है। सैकड़ों सालों से एक चलती आ रही है, बाप दादों के जमाने से एक चलती आ रही है। किसी को हक हासिल नहीं है कि कीमों में रंजिश पैदा की जाए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मजबूती के साथ इस मामले को हल किया जाए। पाकिस्तान हम से कोई चीज कराना चाहता है वह कराए लेकिन हमारे जो मसले हैं उन पर भी तो ध्यान दे, उनका हल भी तो ढूँढे। डिप्लोमैटिक लैवल पर इसको लिया जा सकता है। यह मसला इतना मुश्किल नहीं है कि हल ही न हो सकता हो या लड़ाई से ही हल हो सकता हो। मैं समझता हूँ कि बातचीत से हल हो सकता है। इंटरनैशनल लेवल पर भी इसको लिया जा सकता है। जरूरत हो तो यू०एन० ओ० में इसको उठाया जा सकता है। वह भी

गलत नहीं होगा। यह ह्यूमैनिटी का सवाल है। करोड़ों आदमियों का मसला है।

जहां तक रिहैबिलिटेशन का सवाल है, मुझे पता है गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है और उसको करना चाहिये। बे हमारा खून है, हड्डियां हैं, लोयडे हैं। रिहैबिलिटेशन के मामले में कोई शिकायत की बात नहीं आनी चाहिये। ऐसा अगर हुआ तो हमारी गवर्नमेंट भी बदनाम होगी और पार्टी भी बदनाम होगी।

SHRI N. K. SOMANI (Nagaur): I would not like to go into the political reasons for which this mass exodus has begun because that ground has been adequately covered by Shrimati Sucheta Kripalani. I would like, however, to say that in spite of the fact that this unending trail of human misery has been going on for quite some-time, although the Ministry of External Affairs' intelligence department as well as our Deputy High Commissioner in East Pakistan have failed to send adequate precautionary notice to this Government, when people in thousands and lakhs arrive on our soil, after the event on the part of this Government as well as the Government of West Bengal, there has been not only laxity in the matter of handling this human problem of this magnitude but corruption and nepotism has been allowed to reign among various authorities in the matter of rehabilitation and settlement of these refugees. I think this is a great unfortunate pity. I am told that as long as these unfortunate people do not cross the border of East Pakistan there are goondas and raiders there who are prepared to strip them of the last iota of their belongings, but as soon as they cross into India, there are touts who not only make between these people and various sections of the rehabilitation department but lead them into one camp or another, depending upon how much money is passed through their hands and also whether a particular group of people is allowed to go into Dandakaranya or not or is allowed to rot in other parts of West Bengal. If in human misery and the woes that have been described in this House and in the press before in regard to this affair, we have allowed corrup-

tion, nepotism and bribery to prevail, it is a very unfortunate state to affairs. When stark misery is being traded in where unfortunate people in such numbers are involved, it really becomes a matter of great regret.

Here is what the Bengal newspapers have to say. There is a brief report :

"This whole atmosphere as far as the camps are concerned is stinking. The sight of half naked men and women with sunken cheeks and hollow eyes is demoralising. A woman of 40, Shrimati Radha Rani, with her baby sucking her dry breast broke down as she narrated her woes."

These woes related to her trip after she had arrived in India and not while she was in Pakistan. We have, therefore, got to see that for whatever reasons, political, economic or social, these people have been thrown out of their ancient land, once they are here in India, once we have accepted them, then the utmost has to be done on a war footing, as Kanwarlalji has suggested, to settle them. In this aspect of the matter, I would like to say that the Ministry of External Affairs is the least involved or the most inappropriate to deal with it. I would like that the Ministries of Rehabilitation and Labour, Finance, Industry and other concerned Ministries of the Government of India will have to function in unison so that the problems which have arisen due to this mass exodus are tackled.

17 hrs.

There are two reasons why a survey, and a quick survey, should be held about the kind of people who are coming to India. One is the kind of skills that they have inherited, the kind of livelihood that they have been used to, so that we can easily transform them into equivalent channels if they are available. Another is the kind of potential that these people have, because the greatest help that you will receive in the matter of rehabilitating these people quickly would be a mass transference of skills. Otherwise, if we allow them to rot and do not provide any further training to help them to rehabilitate themselves and earn a livelihood,

[Shri N. K. Somani]

this will continue to cause misery and poverty which has already become the of other millions of refugees who have come to India so far. Therefore, for these reasons this particular quick, not only sampling but, screening of the type of people who are coming into our country is necessary.

There is another reason that has been given by the Government of Assam, and that is that as a result of the mass exodus, certain undesirable people, taking advantage of this particular upheaval, go to Assam for purposes of espionage and other such activities. This is the contention of the Government of Assam, and the Government of India should certainly be a little more careful and vigilant against allowing a handful of undesirable people taking advantage of the situation. All these aspects should be carefully looked into.

A few months back the Chairman of the Board of Rehabilitation, Shri Manubhai Shah, had brought to the attention of the Government of India that there is one major obstacle in the way of the various States of India like Rajasthan, Madhya Pradesh and Orissa which, fortunately, have a little more land and whose population density is not as high as that of West Bengal or other part of India, and that is that the States have to bear 50 per cent of the loss due to non-recovery of loans from these repatriates and refugees. This particular recommendation that the Central Government should bear 100 per cent of these losses on the non-recovery of such loans so that the State Governments do not take it as an unnecessary burden was made by Mr. Shah in the beginning of this year and I would like to know from the hon. Minister whether the Government of India have taken a decision about it.

It was also suggested at that time that a special Development Corporation should be formed for the speedy development of Andaman and Nicobar Islands because there is a tremendous potential for maintaining and improving the various plantations, fisheries, forestry and other industries in that particular area. The easiest transition that can take place from an agricultural economy are

these particular fields for which a tremendous wealth and potential exists in Andamans and Nicobar and the population statistics there also should persuade the Government of India, if they have not yet energised this particular Board, if they have not authorised this Board for Andamans and Nicobar, to do so without further delay.

There are several incentives in our fiscal system allowed by the Income-tax law and Finance Act from year to year where, if certain kinds of activities are done by employers, a loaded income-tax exemption is given in the sense that if Rs. 100 or Rs. 1,000 are spent by a company or an employer for a preferred activity so declared by the Government of India, 125 or 150 per cent of that expenditure is allowed to be written off or claimed against income-tax. Because the employment situation is so difficult in this country, a special incentive should be given to employers both in the public and private sectors so that not only during the training period but also when these people are absorbed in normal industrial and economic activity a little later, such incentive should be allowed to these employers so that we can absorb these unfortunate people in our economic system.

The Government of India, after nationalising banks for the last one year, have been claiming that they have opened credit channels to the needy people, small people, farmers, students and the self-employed. I would very respectfully like to persuade the Finance Ministry through the Minister of External Affairs to see that some of the lead banks, especially those located in West Bengal, come out with special loans and credit facilities for the refugees so that on the one side one agency of the Government should transfer skills as I said through a massive training programme. On the other side, adequate finances by way of loans and credit should be made available so that as many of them as possible can become self-employed and do not continue to remain a burden on the Indian economy... (An Hon. Member : Security?) They say that the security aspect is no longer important and I believe them. It is a question of early implementation of this particular scheme... (Interruptions.)

You will agree with me, Mr. Chairman, that whenever there were national calamities in our country, whether it was famine in Bihar or floods in Assam or something else somewhere the rest of the citizens of our country used to rise to the occasion. For the last few years unfortunately because people—it is my surmise—have lost faith in the policies of this Government no amount of human misery seems to move those who can afford to be philanthropic to raise private efforts. I am surprised that a matter of this importance has not moved the rest of the Indian society because I for one believe that although a lion's share of responsibility for rehabilitating these people lies squarely in the household of this Government independent citizens, businessmen and others also owe a duty to themselves to make private efforts to rehabilitate these people and open the gates of their factories and workshops so that these persons can be taken in. I think the Government should appeal and also discuss this problem with representatives of business and industry and ascertain why they have lost faith in public and philanthropic causes. If it is not too late they should persuade those persons also to join hands in contributing with the Central Government and the West Bengal Government so that the refugees can receive timely succour.

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur) : It is unfortunate and every Indian feels pained at what is happening in Pakistan since partition, almost continuously. Every intelligent Indian has got to make this assessment that good neighbourly relations with Pakistan is an imperative for India to maintain its international image as well as to have peaceful development in our own country. Still we seem to be helpless spectators of what is happening in a neighbouring country. We cannot think of any possible methods of retaliation because that will only worsen the situation. I do not think that anybody in this House would suggest that we have got to retaliate in the same manner as it is happening there and create communal problems in our country. Nor can we think of warfare; we should shudder at it. What is left? Is it only the reminders that the Government of India send repeatedly to Pakistan that will solve the problem? I was shocked to hear the hon. Minister say-

ing yesterday or the day before in answer to a question on this exodus that there was no need for further publicity of our diplomatic efforts more than what we are doing at present. The Government are complacent about it. What they have done in international circles is pretty little. Because of their bungling they are not able to mobilise international public opinion as to what is happening in Pakistan. What is happening in Pakistan is, I should say, worse than apartheid. At least in Africa, we know that the people continue to live there in spite of the difficulties, but here it is a continuous trickle of people coming to India, and you have totally failed. I do not want to speak on the question of rehabilitation because that really does not pertain to the Minister here and that has also been dealt with at length by my friends. Also, I do not want to go into the details of what is happening in Pakistan. We all know it by and large. There may be a little exaggeration here and there; we all know the tortuous experience that the minorities are going through in Pakistan. I want to concentrate on one aspect, particularly on our failure to mobilise the international public opinion and to bring pressure on Pakistan to realise the hard facts of international life.

I may have to speak about certain harsh truths and I hope the Minister of External Affairs will have an open mind to appreciate my points. I happened to be in one of the delegations which went to the middle east in February last. To my utter dismay and shock, I found that even in Egypt which is considered to be our best friend, the public by and large, are not so well disposed towards us as they are towards Pakistan. If you compare the feeling that exists in the minds of the populace there, as to how they react towards the Pakistanis and how they react towards Indians, you will find that they have got a better appreciation and affection towards the Pakistanis than towards us, Indians. I do not mean to say that they do not have any affection towards us. But if you take it in relative terms, you will find it so. When our embassy gave a party and when we happened to meet the housewives of our embassy people there, we learnt this. The diplomats, of course, were clever people, and that is so because they are trained for

[Shri S. Kandappan]

it. When I asked them how those people in that country reacted to us, they said "we are all friendly." But when we talked to the housewives, every one of them, told us in no uncertain terms, very clearly and categorically, that it is their experience—whenever they go shopping or when they meet other womenfolk—that they are more fond of Pakistan and well-disposed towards the Pakistanis than towards us. I tried to find out as to how it happens. It is definitely not because it is in the middle east and they are all Muslims countries; it is not deliberately because of their religious affinity or because of their attachment to religion. It is not as if they hate us deliberately because of that. It is far from that. Actually, it is because of the propaganda that Pakistan carries on through the radio and through the press and her diplomatic efforts against our country. Not only that. We do not do anything to counter that propaganda at all. In some of the places, in fact, in Sudan and elsewhere, when we asked some of our people who should know these things, they are in the dark about certain basic facts. They are not even aware of the fact—even the people working in our embassies—that India has got the third largest Muslim population in the world. They do not know that. When they themselves do not know it, how are they going to carry the impression to the country in which they are serving? There is no use of your claiming that you are secular. In the outside world, particularly in the Muslim countries, if you cannot make these people carry this impression and put across these facts to the people in those countries, how can you succeed? You should let them know that India has got a sizeable section of Muslims; it is not a small number; and they enjoy equal rights with other people along with the Hindus and others. If you cannot carry this impression to the countries abroad, how are you going to succeed in countering the pernicious propaganda that Pakistan is indulging in?

MR. CHAIRMAN : Your time is up.

SHRI S. KANDAPPAN : Sir, I have two or three more minutes. I hope I am making some useful points. If the hon. Minister of External Affairs has got an open mind, it will help him.

MR. CHAIRMAN : Please listen; my difficulty is the limited time; the time allotted is only two hours, and if every speaker exceeds his time, then it will become very difficult.

SHRI S. KANDAPPAN : Nobody can finish his speech in two or three minutes.

MR. CHAIRMAN : It is the Speaker's orders.

SHRI S. KANDAPPAN : In that case, let us extend the time for this. (*Interruption*).

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta North East) : At least the spokesman of the parties should speak, and then you can think of the other speakers. You cannot compel a Member to finish his speech in just two or three minutes.

SHRI SHRI CHAND GOYAL (Chandigarh) : In the other House—Rajya Sabha—this was discussed for a whole day.

MR. CHAIRMAN : You have spoken for six minutes already.

SHRI S. KANDAPPAN : Now, Sir, we had another experience in Algeria when we were supplied with an interpreter from our Indian embassy, when we went to meet the Foreign Minister there. In most of the middle-east countries—there are about a dozen of them—the Arabic language is the official language and is predominantly spoken. Within a few minutes we found that the interpreter we took with us was not upto the mark in translating our questions and the Minister's answers. It was very embarrassing for us and after a few minutes the Foreign Minister of Algiers asked one of his men to be the interpreter and our interpreter was brushed aside. It may be a small incident, but you imagine it. The Indian students go to Cairo and other places to study the Arabic language and the Islamic culture which is identified with their language. Such a poor performance on our part exposes our inability and inefficiency and is bound to create a bad impression. Our claim of interest in Islam and its culture when we are not even able to master that language and speak fluently in it would naturally be suspected. It is not a small thing.

Our Foreign Minister seems to think that diplomacy means communication to our Ambassadors and *vice-versa*. Of course I am a novice in international politics, but my common sense tells me that all over the world diplomacy is more than that. Every country tries to reach the people across. During the 1965 Indo-Pak conflict, without any provocation, the late Dr. Sukarno said that he was even prepared to send his navy in favour of Pakistan. Why? It was because of the public mentality there and psychology that prevailed in Indonesia. We have miserably and criminally failed to counteract the propaganda of Pakistanis. Nothing reached the people of other countries from our stations. Only after that, from Tiruchi and some other stations they have started broadcasting in Malay language to reach the maximum number of people in South-East Asian countries. If we make a little effort, I am sure we can counteract the Pakistani propaganda. It is simply by diplomatic manoeuvring that they are able to succeed against us. It is not that everywhere in every country they think that Indians are by and large brutal, cruel and barbarous and only Pakistanis are noble people. I do not blame any country if they have that impression because they have no other way of knowing what is happening in India. You do not provide them with enough media to appreciate the Indian position.

Somebody referred to Ceylon. I am actually conscious of the bungling of the Government of India. The Indian problem is the problem of Tamils in Ceylon. Sentiment, religion and language are involved. The present Prime Minister of Ceylon unfortunately has got an impression that Tamils in India, particularly the DMK, have got sinister motives in Ceylon. When sometime back the previous Prime Minister of Ceylon was invited to India, when there was protocol arrangement, I suggested that he should be brought to Madras, so that he may have contact with the Tamils there and see for himself what an amount of goodwill Indian people have for Ceylon. But we have missed that opportunity. During the 1965 conflict, there was a dangerous pamphlet circulated by the Pakistan High Commission in Ceylon distorting historical facts. None of our embassy people bothered to counter

it. Unfortunately I do not have that pamphlet with me now, but in that they said that Tamils from India are always enemies of Sinhalese. The historic truth is far from it. There is enough evidence in Sinhalese history itself to show that they have been living like brothers for centuries. But the Indian Embassy there did not bother about it. These are very vital things to my mind and unless they wake up to the realities, I am afraid, the situation is going to continue. India cannot afford this luxury of taking numbers of people from all sides. No country throughout the world faces such an exodus problem as India is facing today. It seems to be a continuous problem and the way we act seems to tempt other countries to create such a situation. Even where there is no problem suddenly one finds morning problems are cropping up. Other countries seem to think that wherever Indians are living India would be prepared to take them back. Is there no international law? Can't we take it to the forum of the United Nations? Can't we do something about it? Problems of this magnitude faced by an under-developed country like ours should draw the attention of the international community. We should try to create a forum at the United Nations. I do not think it is an impossible task. I am sorry to say that the diplomacy of the External Affairs Minister in this field is a total and complete failure.

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI (Krishnagar): Mr. Chairman, Sir, today in the month of Bhadra we are discussing the problem of the refugees coming over to Bengal from East Pakistan. The dark rain clouds have been made darker by the sight of the lakhs of homeless people. At this time of heavy rains in Bengal the tears shed by the refugees have made the heavy rains heavier. It is on such sad circumstances that we are discussing this problem. The storm clouds are indeed dark over Bengal.

I would like to say that there has been some effort perhaps from the side of the Government of India to solve this problem. I do not think that the Indian Government is doing nothing. But there are certain

[Shrimati Ila Palchaudhuri]

thing which is absolutely imminent for them to do. I must say that there is one ray of hope. I understand our External Affairs Minister has contacted the External Affairs Minister of Pakistan. What the correspondence has been, what the answer has been, I do not know. We are told that they are encouraging. Encouraging to what extent? Has the influx stopped in any way? We would like to know that.

Secondly, when we sit down to a conference table we are always browbeaten by Pakistan who says; let us discuss Farraka, let us discuss Kashmir and thrash them out before we can solve other problems. Let us insist that this live human problem be solved first before we can discuss anything else. The problem of the waters of the Farraka or the Kashmir question can be solved later but this human problem brooks no delay.

You will see from the figures that out of the total number of 1,45,595 refugees who have come from Pakistan 1,35,950 have come to West Bengal. So, you can imagine the stress and strain on the economy of West Bengal. If you take the figure from 1964 onwards it will come to over six lakhs. So, the economy of West Bengal as it is today has been strained to the utmost. Therefore, the whole problem has to be looked at from the national angle and all the refugees must be properly rehabilitated. What is still more depressing is that political capital is being made out of human misery. My hon. friend opposite has suggested that businessmen should try their best to absorb the refugees from East Pakistan. The businessmen would be quite ready to do that. I have myself talked to some businessmen and I know that they will do it. If politics is kept out from refugees, if the refugees are not induced to hold all kinds of demonstrations in front of business establishments, I am sure businessmen would come forward not only in hundreds but in thousands to absorb these refugees from East Pakistan. But the political parties must realise that human suffering is not a thing from which they should make political capital. But there are many parties which are making it today.....(interruptions) Ask the r fugees themselves if the CPM is not doing

it. Secondly, I would like to stress the point, that Pakistan makes the most pernicious propaganda about India. Every little incident that happens in India is magnified a thousandfold and we hear of all kinds of tales of genocide, this and that. Of course, communal trouble sometimes flares up here and there but India has declared herself to be a secular state and we take full responsibility for our Muslim brethren. There are more Muslims in India than in either part of Pakistan, East or West, and they are residing in India in peace except sometimes when some trouble flares up. But propaganda is carried on by Pakistan and we hear of genocide in India. But where is our propaganda? What have we been doing? Our propaganda machine does not say what is happening in Pakistan.

Let me come to the human problem. Let this problem be taken to every international forum to the UN, the Human Rights Commission and everywhere to mobilise world opinion. The Minister has said time and again in the Hous that we have "nothing to gain by taking it to the UN." but I certainly feel that if we can mobilise world opinion the UN is one of the forums where we can usefully do this. I hope that it will be taken to the Human Rights Commission and to the UN and our propaganda is made stronger so that the world knows what is exactly happening in Pakistan which has declared itself to be an Islamic state and wants to squeeze out people of all other religions.

Lastly, what is happening in the Hasnabad and Basirhat areas? It is a sad state of affairs even today. Out of the refugees that have come there, how many have been dispersed up to date? I find from the figures that up to date the total number of dispersals is 84,573 whereas lakhs have come. I have been round to Hasnabad and Basirhat. In this month of Bhadra, as you know in Bengal it is either terribly hot or it is raining heavily. I have already written to the Prime Minister that the tent supplies are inadequate. About the *bashas* that have been made, there is very little to say. Human excreta is so horrible that pollution is something unheard of; you will refuse to believe it. 15 to 20 children die every day

owing to this infection. Of course, the Government is making efforts in that direction to inoculate people and so forth, but it is inadequate.

From the list we have been given, I find that some 700 tents have been supplied and another 600 tarpaulins have been asked for. This is absolutely insufficient and will serve a few hundred people. The Rs. 34 lakhs given 'on account' to West Bengal Government is also entirely inadequate to rehabilitate these displaced persons. West Bengal, Sir, will ultimately need anything up to Rs. 100-200-300 to 400 crores if they have to be rehabilitated. They constitute the people who are feeling frustrated. They have left all that they had behind and here they have not found anything.

As to what is happening to the women while they cross over the border, even as they come into India, it is really shameful. Some of them have been degraded, misused and all kinds of things have been done to them. Even after they have come to India there is no safety for the younger women. I think, they must be well guarded and the women must be made to feel that at least they have come into a society where womanhood is honoured. I will appeal to the Minister to put better vigilance there to see that they are taken over the border safely and what little belongings and jewellery they may have been able to bring over are not snatched away from them from the other side of the border. This is happening daily.

Also in many cases, their visas and passports are not in order. Let us not be technical about it. There has been the case of a woman who had to leave her child behind because his name was not included in a hurry in the slip. If there is a child whose name is not there, let the mother not suffer more with all the suffering she already has. The mother should be helped to bring over her child. Of course, in this case she was able to get her child across the border ultimately. But the agony of the mother during all that time can be very well imagined.

The medical facilities are also meagre. Various voluntary organisations that are working encouraged. The idea that if we let the Congress organisation work, then

we will have to let other parties work should not be the consideration. The Bharat Sewak Samaj, Ramakrishna Mission the women's Coordinating Council etc. are doing very good work and they should be encouraged. We can supplement the Government work.

The first and foremost thing that remains to be done is about our attitude. We do not want war. But we want every kind of discussion between the two countries. Let the two Ministers, Shri Swaran Shingh and his counterpart in Pakistan meet, if possible, and discuss the problems across the table. Let us insist that we discuss this human problem first before we take up any other question so that human misery can be stopped. It is pointless making-rehabilitation plans, putting them here and putting them there.

I would also particularly emphasize that when you rehabilitate them, very often they come away from the camps. They are huddled together and sent back like cattle. They are asked, why have they come? We never think of the reason, why they have come! They are the people who used to have enough water and they used to have beside the beautiful rivers of East Pakistan, the Padma Dhaleshwari and Maghna. And they are being put in dry places. They cannot live without water. You rehabilitate them where they can get water, where there is some work to do and where they can live. Let India accept them. At the same time, let us do some thing to see that this influx is stopped which is unfair, barbarous, Communal and absolutely inhuman.

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta-North East): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I shall try to speak telegraphically because there is very little time.

About 150,000 fresh migrants have come in the last six months and the Minister of Rehabilitation tells us that he expects about 180,000 more who are waiting to come across. The first job is, if they come and when they come, to give them relief that is necessary, to disperse them wherever we want to send them and then to rehabilitate them. These are the three jobs to be done.

[Shri S. H. Mukerjee]

As regards rehabilitation, I am afraid, it is still pending in the case of 8 lakhs of old migrants who had come after 1964 and now we have this addition of numbers. It will be very heavy job. In regard to immediate relief, whatever reports we have been received are very disquieting. Harrowing conditions have been reported by everybody and I do not want to add to the sentimentalism in the House by giving instances of distress. But the fact is that harrowing conditions have prevailed. One instance which I was given was that at Hasnabad till the other day at least there were 60,000 refugees while rations were being supplied to only about 13,000 refugees, and that where the people were living, there was no cover and no place to live a human life.

The hon. Minister told the Rajya Sabha the other day that the principle responsibility for the administration of relief was with the West Bengal Government. The West Bengal Government and the Central Government are today, more or less, the same kettle of fish. But I fear in West Bengal some superannuated officers are in-charge who are utterly unfit by temperament and by training for this kind of job. It requires a human approach. I would suggest that at least one of the two Ministers, Shri Sanjivayya himself or Shri Bhagwat Jha Azad should go and settle down in West Bengal for a short while at least till the crisis is over.

We have been told by the hon. Minister that he agrees that in so far as West Bengal, Assam and Tripura are concerned, the saturation point has been reached and, therefore, the other States must help in a big way.

Shri Sanjivaya has told us that nearly one lakh refugees are going to be taken charge of by several States which have already offered. The only difficulty is that a State like Madhya Pradesh has offered land in the Chambal ravines which might be rather a difficult proposition. It is exactly here that I would like to remind our friends of different persuasions who talk so much about all India being one and that sort of thing. Here is an acid test that all the other States really and truly come forward to assist people in distress who happen to

be Bengalees. Let all of them come and do it. Till the other day the West Bengal Government has been saying that they will go as far as possibly can but it is not physically possible to settle every body inside West Bengal. Therefore, you must all come and do something about it. Government must do something about ancillary occupation apart from agriculture to which most of these people are accustomed and for that purpose whatever confabulations are necessary in government before execution of programmes should begin, they should start. And this reminds me of what the Chief Commissioner of the Andamans had expressed against the settlement of the refugees in his part of the country, in Nicobar in particular and the argument given was that these Bengalees cannot be settled and should not be settled in strategic areas. This is a very strange proposition.

SOME HON. MEMBERS : Shame, Shame.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Call him back. Send him out.

SHRI H. N. MUKERJEE : It has been reported repeatedly that the Chief Commissioner of Andamans said it and the ground given was that for strategic reasons you cannot rely on Bengalees and they may not be a stable and reliable factor. This is a dangerous and defamatory notion and Government must do something about it.

I come to the other factors in regard to the causes that have brought about this business. This is a continuing sore in our body politic which leaves everything in tense and distressful condition to all of us in this country as well as to a certain extent in Pakistan. There is no doubt about it that perhaps the main reason is economic distress particularly in the contiguous areas of Jessore and Khulna districts of Pakistan where the distress is more acute and possibly the idea that perhaps in India conditions might be better might have gripped the minds of some people. Apart from the causes listed, namely, the insecure conditions there and economic distress and discrimination against the minorities we must remember that the main cause has been something which somehow is being sought to be low-lighted. Even when Shrimati Kripalani was speaking, I noticed that she

did not stress that factor which is the most important of all. We have to remind ourselves that our record being what it is ... it is bad enough ... we should be very careful that on no account must communal passion be roused over this issue in our country. I am not going into that aspect of the matter. I am referring to what is a shining new phenomenon in East Pakistan to-day to which testimony has been brought by no less a person than Maharaj Chakravarti. He was mentioned by Shrimati Kripalani. But I am sorry she did not go on to say that repeatedly speech after speech Maharaj Chakravarti who has spent 30 years of his life in jail and who has come over here as an honoured guest of this country ... he has chosen to live with his people in Pakistan and not come over here and he has lived 30 years in British jail and Pakistani jail... he repeatedly said in speech that the atmosphere in East Pakistan is one of the utterest friendliness for India, that among the students, among the youth, among the surging masses of the people who are trying to have a new life, there is an idea that we must have friendship with this country and I am sure he has appealed to our people here not to be led by reports of whatever is happening there and not to be misled by this migration which is a distressing proposition enough to-day and do anything which might damage this perspective, this developing perspective of a possible friendship between India and Pakistan. This is something which is terribly important.

I got from the External Affairs Ministry Which brings out the *World Press Review* from time to time, an extract from a foreign paper ... we prefer things foreign on many occasions...the *Scotsman* of the 13th of June, which talks about this right-left clash which is coming in Pakistan and it says that 'It is a bewildering transformation.' I am quoting its exact words. It says :

"Looming over everything else in East Pakistan is the clash between right and left, between parties of the *status quo* and parties that want a change."

This is the position. So many other things I could quote, but it is not necessary.

It is on account of this that *Yahya Khan* and company who want to perpetuate their position that they are using certain mechanisms in order to bring about some sort of disturbance in the minds of the people of Pakistan and feeling of hostility against India and also to make India hostile towards Pakistan so that it is easier for them to continue their position.

So, there is in Pakistan a conspiracy which is certainly conducted by those people who are in power there...the conspiracy to shift some people from Pakistan into India. It is on account of this that such a thing has happened.

Recently in Pakistan, over the Tagore Anniversary and Nazrul Islam Birth Anniversary there was such demonstration of affection and goodwill for India and for Bengal in particular which has been shown that we share the same feelings in the east and west in my part of the country. It is a magnificent phenomenon of which if we do not take advantage we should be trying the interest not only of India but of the cause of peace in our part of the country. This is therefore, Sir, something which is terribly important.

I am afraid I did not quite understand this. I came a little late yesterday to listen to the External Affairs Minister answering certain questions. Did not our Deputy High Commissioner and his office have intimation about these matters? Did they not know about these things? Don't they give advance intimation about the kind of atmosphere in the country and don't they give some kind of advice? Has not the Government of West Bengal been instructed by the Government of India to do something to take advantage of this feeling of friendship? Could not we send Writers' delegation to East Pakistan at this point of time, when in East Pakistan in particular the democratic upsurge is so very much in evidence so that steps could be taken in order to stop the kind of distressful happening which have taken place when they did not inform the Government in regard to the possibility of doing something important about this position? Was Government unaware of this sea-change, so to speak, in the atmosphere of East Pakistan? And,

if Government did know, why was it caught so dismally happening ?

Sir, that is the position to which I hope the Government would give us some sort of response.

Now, Sir, I know that there are some people and Mr. Kanwar Lal Gupta while opening the Debate, give a particular twist to the entire discussion which was unfortunate.

We should not huff, a huff which is deliberately fanned by some people in the House as well as in the country, and we know who they are. We should not be in huff and take a negative stand regarding the solution of our outstanding problems.

We do happen to have outstanding problems, whether it is trade with each other or Kashmir or river waters or minorities. It is a fact whether we like it or not that we do have outstanding problems and these outstanding problems have got to be settled.

It is an irresponsible and in the circumstances of today a criminally reprehensible demand if we ask for territory from Pakistan to settle the refugees. Such talks hit the headlines in the Press tomorrow but they do the greatest injury to the cause of our country as well as the cause of peace in our part of the world.

It was a small mercy that Shri Kanwar Lal Gupta conceded when he said that he did not like the idea of exchange of population. I am very grateful that he has that he does not like exchange of population. But he wants this business, of some land from Pakistan. Sir, if it was so easily had, nobody would have any objection. But, let us not do this kind of thing. We cannot even give land in the Andamans to the refugees but we are asking for land from Pakistan.

Sir, I am reminded of what has been said by so many Members here. Why it is that our image is so bad ? (*Interruption*) I will conclude in a couple of minutes. I know my time is up.

This is essentially a bilateral problem which we have to solve. I do not want this matter to be raised in the United Nations as so many people have asked for because we know that the United Nations Organisation is like. For a variety of reasons, we have never been for given our freedom by the imperialist and the neo-imperialist powers of today, and they will take a certain attitude against us. Besides, we live in a glasshouse, and we cannot do very much about it. Going to the UN or to any comparable organisation might rebound us in a bad way. It is not necessary for us to go to the United Nations, but the world should be kept informed of the fact but not in a captious way or in a fractious way, that India has a terrific and overwhelming and stupendous refugee problem. We do not even tell them about it. We tell them more about what we do to the Tibetan refugees, but we do not tell the world that we have no our hands so many million refugees who have had to be rechabilitated; we do not even tell them that. But we have to tell them in a self-respecting way.

Do not go with begging bowl before the UN or any comparable organisation, because they will give you the order of the boot; there is no doubt about it. If Jan Sangh goes and argues the case, they will know what to accept, and in view of the image of India being as bad as it is on account of a variety of factors which cannot be discussed now, we cannot except anything happening on account of that.

So why should we not continue a policy of bilateral discussion, really and truly ? Even if we have provocations, we should come forward, offer the hand of friendship and ask for talks in regard to the trade restrictions being removed, in regard to the river waters problem, in regard to common tackling of the problems of the eastern rivers, in regard also to the other problems which are agitating the relations between our two countries. There are the two methods. Do something for God's sake in order to really and truly have relief and rehabilitation properly, and from the long-range point of view, do follow policies of friendship for which in East Pakistan, a climate has been created, and if we do not take advantage of it, it would be a terrible crime for which we shall have to be answer-

able to history.

SHRI JYOTIRMOY BASU : (Diamand Harbour) : While speaking on this, we can not ignore the fact that the refugee problem is an outcome of the Partition of the country which took place due to the impatience of certain national leaders and the present party in power. (*Interruptions*). At that time, the national leaders and the people in Government gave certain assurances which sound so hollow today particularly in West Bengal. Today, it is a mere lip-service. We had the Prime Minister in Calcutta on the 17th, and the whole area is within about 35 miles from here. We have heard about helicopter flights quite often about her, but in this case, she had not had any time because she was busy politicking and intriguing and planning repression in West Bengal. They are anxious even to co-operate with East Pakistan in the matter of giving over-flying opportunities to the troops to suppress the agitations of students in East Pakistan. We know that our Government are anxious that progressive movements should not gain ground in East Pakistan. So, it is no use hiding that fact from us. Today, in both the countries, you have the same pattern of Government, namely the landlord bourgeois class ruling both the countries. So, a permanent solution is not an easy task. But at least we must be sincere in trying to normalise the relations. I am quite confident that Delhi has really not tried to normalise relations, the relations of trade, travel and culture. What we see today is that people in West Bengal are suffering in the same manner in the hands of Delhi as the East Pakistani people are suffering in the hands of Pindi. There has been recently an article in the *Pakistan Observer* advocating normalising of trade. We are very grateful and very thankful to the writers of that article that they are trying to get things straightened out so that those miscreants cannot play mischief for very long.

This is a fresh influx. Why is this happening? It is happening because it is being done by reactionary forces, backed by Pindi. Scores of *agent provocateurs* are roaming about in the villages trying to terrorise people and pushing them out. They are even telling them 'if you go to India, you would be getting money and land and your miseries will be over'. There had

been some partial crop failure in certain districts, and they have taken the opportunity. I had been to the border areas, and I have spoken to the refugees. Let me cite to you just one instance. I saw a man and asked him 'Why did you leave your country?' 'He said 'it is very difficult to live. The Muslims are making things difficult for us.' I said, 'Tell us why you left.' He said: 'A man came to my house one evening. He had a *biri*. He wanted to light it and ask for fire. So he went to the veranda. The woman in the House got frightened. She pulled her veil and ran away from the place. So the man with the *biri* went near the kitchen and lit his *biri* on the oven. That was bad enough. There has been no communal riot there, there has been no cause for trouble, no provocation.....'

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : All absurd. There have been enough provocations. He can say that there has been no communal riot. But we know what has been happening (*Interruptions*).

SHRI JYOTIRMOY BASU : I am speaking on my own responsibility. He can say what he wants when his turn comes.

SHRI SAMAR GUHA : I have noted 500 case histories. I know what has been happening. (*Interruptions*)

SHRI JYOTIRMOY BASU : We know that the students' the progressive forces are not doing anything wrong. These men have also been given a threat by these *agents provocateur* that if in the October 1970 elections they voted for Mujibur Rehman's Progressive party, the Awami League, they may have to pay the price for it. All these things have been spread. But there has been no immediate riot, there had been no basic cause for provocation. I have meet and talked to 50 people in two days and spent no less than 20 hours with them.

SHRI S. S. KOTHARI (Mandsaur) : Then why are they coming in such large numbers?

SHRI JYOTIRMOY BASU : We know his colour; let him keep it to himself.

Daily we are having 1,500 to 2,000 migrants. They all belong to the Namasudra

class, the Scheduled Castes who have been trying to stay in their land of birth. But here this Government has failed the country and the migrants wholly and miserably. I am making this charge against Shri Swarn Singh, the External Affairs Minister. He has no right to remain in the chair because he has utterly failed to caution the Ministry of Rehabilitation in advance about this influx. Why is he maintaining a High Commission office in Dacca? Why is he having his establishments in East Pakistan? Was it not their duty to caution Government that this sort of thing was going to take place? Because that duty was not discharged, we see more miseries.

Today we see in the machinery of Government, as Prof. Mukerjee has very rightly said, an old superannuated variety of civil servants in West Bengal looking after the refugee problem. They have shown no trace of human compassion. I am ashamed at the way the migrants are being treated in respect of their basic needs of food, shelter, medical care and other human needs. One has to hang his head in shame before any civilised person at this treatment meted out to the migrants.

On the other hand, we see communal, reactionary forces making hay while the sun shines; They are shedding enough crocodile tears.

There are three different jobs to be done. Shri Sanjivayya may make a note of this, though I believe he knows it. One is reception at the border. The second is dispersal and the third is rehabilitation. In regard to the first, I have seen the most glaring instances of failure. I have seen families exposed to Bengal's torrential monsoon rain and the scorching sun for days. Shri Swarn Singh and Shri Sanjivayya have beautiful air-conditioned hongs in Delhi to maintain each of which the country pays at least Rs. 30,000 p.m. But one has to go over to the border and look at the way in which our flesh and blood, kith and kin, are being treated. I have seen them exposed to torrential rains for three consecutive days. I have seen them exposed to the scorching sun. Then what happened afterwards? They were provided with some sort of half covers plastic sheets of a very thin variety. You can crawl into it, but when

the big showers came everything was flooded. There are no latrines, sanitary arrangements are unknown, water supply is very inadequate, and as a result they are rushing to the cities, and in Scaldah Station the whole floor space is covered by these unfortunate refugees, men, women and children, tottering old men huddled together like rotten pieces of sardines. You ought to be ashamed of yourself that you belong to a Government that has treated humanity in this manner to day in the twentieth century. You talk about socialism, you talk about welfare state, all humbug, just to get votes and give stunts to the people of the country.

What is being given to them? Not all of them are given, but those who are given get only a portion of it. Those who cook their meals are given 300 grams of rice, 30 grams of lentil and two pieces of onions. Mr. Swarn Singh's dogs are given better meals I can assure you, if he has any. Where they are given cooked meals, as in Bongaon, it is one meal in 24 hours to a 300 gram of rice. Nothing special for the children. If some big man wants to get rid of sub-standard, bacteria-infested, old, outdated milk powder, that is given there. There is milk for the children, no fuel for cooking. And to find fuel, they are entering local gardens and there are minor clashes quite often. You have a big number of Muslims in that area, very law-abiding, peaceful, loyal Muslims and they are being vexed. I am sure a day will come when this will pose a problem for us. How do the Government expect a man to cook his food without fuel, without vegetables, without soap to maintain himself, kerosene for little light in the evening, cloths and personal needs? This is what is happening to-day.

But you see the vigorous foreign agencies functioning there like CARE which has been thrown out of Ceylon, because it is a subsidiary of the CIA by Mrs. Bandarnaik I congratulate her, and CASA. It is border area, very sensitive, but they are all there, and the Government of India dares not touch them because their grand-fathers are sitting in Delhi, they will give a twist and these people will start crying. Are they coming here for charity with American church money? They want to create trou-

ble. Why is it that you require these foreign agencies to distribute and go in the midst of the refugees when you by the Food Corporation of India? Because your rice is given them to fish in troubled waters in Bengal.

Look at the dispersal programme, how miserably they are failing. If we say that 1½ lakhs was the total arrival till 10th July, they have not been able to get rid of more than 50 per cent. They are all huddled together, and that is going to create tension, and that will create trouble for all of us. There will be more arrivals, and they must do something.

What is happening? They are sending some of these people to Bettiah and one or two other camps. The arrangement there are very poor; no walls, no latrines, the officials are rude, and they are coming back to the big cities of West Bengal, and that will create problems for all of us. For Cachar, North Bengal and Tripura we are not aware of any arrangement, I am told the arrangements are not there.

The Prime Minister must call a Chief Minister's Conference at the national level and demand of the Chief Ministers to take their quota for rehabilitation, and nobody should be allowed to give any pretext. If you talk about national integration, how is it that you have sacrificed this part of the country and the people? When you have taken the power, what right have you got today to refuse place and shelter for the refugees?

18. hrs.

We had been to Andamans last year. There is very good scope there for resettlement, but if you listen, to the bureaucratic ghosts of the Home Ministry, they have been posing the security problem saying that if you allow these Bengali refugees there, they may not be hundred per cent loyal. This is what the Britishers used to say: Bengalis are non-martial people, unreliable; keep an eye on them; do not allow them to go to sensitive areas. There seems to be the same thinking. How do you expect things to move? The Andaman development programme must be taken in hand with great hurry. We must take immediate steps to shift refugees straight from the dispersal

camps to Andamans where the climatic conditions are suitable for a person coming from East Pakistan. Mr. Vajpayee, as Prof. Hiren Mukerjee pointed out, talked about Butalia; who said, "we want strongly built good Indians to go to the border areas". Mr. Vajpayee agreed to that; and he is of the opinion, I take it, that the Bengali refugee should not be sent to Andamans, particularly to certain islands. May I say to the Jan Sangh which sheds crocodile tears...(*Interruptions.*)

SHRI KANWAR LAL GUPTA : It is absolutely false. He is misguiding the House and I deny his allegation on the floor of this House.

SHRI JOYTIRMOY BASU : Views were expressed that, because of the condition in East Pakistan, a large number of migrants would not find it convenient to obtain travel documents and were, therefore, coming over to India without such documents and that they should also be registered. We should like people not to be harassed under any pretext.

About the old refugees, we heard that there were 507,000 applications from West Pakistan refugees and they were paid Rs. 192 crores by way of compensation and we were happy that it was done. But in the case of East Pakistan refugees it was almost next to nothing. Out of a total of 46,55,030 refugees, 25,99,000 have got no benefit at all. West Bengal needs nothing short of Rs. 250 crores for the resettlement of the refugees. According to the existing order of the Government of India, they are not willing to regularise the squatters' colonies formed after 31 December 1950. It is most unfortunate. It should not be done. May I suggest as my last point that a parliamentary delegation should visit the border area so that they can see things for themselves and come back with the correct impression. If necessary they, the MPs' should also be taken to the dispersal camps and made to understand what specific arrangements the Government are making. Mr. Sanjivayya should either go himself or his State Minister should have an office in Calcutta or near about Basirhat of Hasanabad so that these things could be supervised directly. Decisions should be taken on the spot so that human misery could be reduced to the minimum.

SOME HON. MEMBERS *rose*—

visory Committee.

MR. DEPUTY-SPEAKER : This is a question on which Members are so much agitated and there is a long list of Members who want to speak. We shall have to continue this debate on the next occasion which will be decided by the Business Ad-

18.05 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, July 31, 1970/Sravana 9, 1892 (Saka).